RNI Reference No. 1328500

द रीव टाइम्स

The RIEV Times

हिमाचल,
वर्ष 1/ अंक 1/ पृष्ठ: 16
मूल्य: ₹ 10/-

शिमला, रविवार,
1-15 जूलाई, 2018

www.therievtimes.com

मिशन रीव बनेगा ग्रामीण विकास का सूत्रधार: डॉ॰ एल.सी. शर्मा

गांव में 60% लोग हाई बीपी के शिकार

हिमाचल के अधिकतर लोग रक्तचाप और शुगर से ग्रस्त

शिक्षा के क्षेत्र में दूसरा दर्ज़ा रखने वाला हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य की दृष्टि से एक भयावह स्थिति से गुजर रहा है । यह खुलासा मिशन रीव के अंतर्गत चलाए जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रम के आंकड़ों से हुआ है । 12 ज़िलों के 52 विकास खण्डों में विगत दो माह में ब्लड-ग्लूकोज़, ऑक्सीमीटर, टाईफाइड, हैपेटाइट्स बी, मलेरिया, सिफ़लिस, ब्लड प्रेशर आदि 12 प्रकार की प्रारंभिंक जांच से 11458 लोगों के आंकड़ों के अनुसार 56.68 प्रतिशत लोग उच्च रक्तचाप के शिकार पाए गए हैं जबकि 17.4 प्रतिशत लोग ऐसे पाए गए जो हाई तथा लो दोनों ही प्रकार के ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं । मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य स्लेट के माध्यम से प्रारंभिक जांच की जाती है । इसके लिए मिशन रीव ने देश की अग्रणी संस्था पब्लिक हैल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआई) नई दिल्ली से क़रार कर 150 स्वास्थ्य स्लेट मिशन रीव में सम्मिलित किये हैं ।

स्वास्थ्य स्लेट में प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवक अपने विकास खण्ड की विभिन्न पंचायतों का भ्रमण कर लोगों के घर जाकर उनके स्वास्थ्य की जांच करते हैं और तुरंत रिपोर्ट देते हैं तथा आगामी प्रक्रिया पर डॉक्टर के परामर्श के आधार पर सलाह देते हैं । पिछले दो महीनों में मिशन रीव के स्वास्थ्य सेवकों द्वारा की गई जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं ।

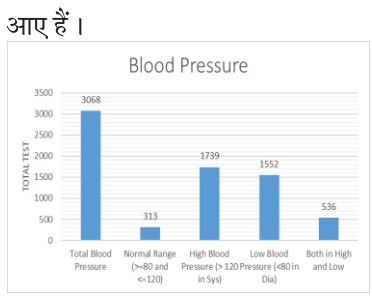

क्या है स्वास्थ्य स्लेट

स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य स्लेट प्राथमिक स्वास्थ्य जांच का एक सुगम एवं सरल माध्यम है । इसमें एक किट होती है जिसमें एक टेबलेट, स्ट्रिप्स आदि शामिल है । रक्त की बूंदों की जांच का पूरा परिणाम रिपोर्ट के रुप में टेबलेट में आता है जिसे लिखित और व्ट्सऐप या ईमेल आदि के माध्यम से भी भेजा जा सकता है ।

इसके अंतर्गत होने वाली प्रारंभिक जांचों में बीपी, शुगर, एचबी, हैपेटाईटस बी, डेंगु, मलेरिया,सिफलिस, आदि शामिल हैं ।

Total Blood Glucose	2541
Normal range >= 80 to <=120	1373
High Sugar (>120)	1103
Low Sugar (<80)	65
Non-Fasting >120	1020
Non-Fasting <80	25
Fasting >120	83
Fasting<80	40

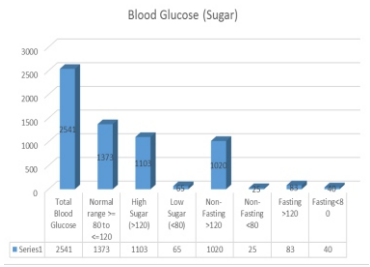

Total Blood Pressure	3068
Normal Range (>=80 and <=120)	313
High Blood Pressure (> 120 in Sys)	1739
Low Blood Pressure (<80 in Dia)	1552
Both in High and Low	536

हिमाचल के गांव में लोग शुगर के मरीज़ों की तादात भी बढ़ी

स्वास्थ्य स्लेट प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा

इन तमाम जानकारियों का पता तब चला जब स्वास्थ्य स्लेट के स्वास्थ्य सेवक गांव में चेकअप/ प्रारंभिक जांच के लिए पहुंचे । प्राथमिक प्रारंभिक जांच में अस्वस्थता का पता चलने पर उन्हें रीव क्लिनिक मोबाईल लैब में जांच हेतु परामर्श दिया गया तथा लैब की रिपोर्ट के बाद रीव के विशेषज्ञ डॉक्टर के पैनल में आगामी उपचार हेतु भेजा जाता है ।

केस स्टडी

सीमा चौहान
गांव कोहबाग

मुझे 6 महीने से सिरदर्द रहता है। कई बार डिसपैंसरी से दवाई भी ली लेकिन यह पूरी तरह से दूर नहीं हुआ । मिशन रीव के सेवकों द्वारा की गई जांच में जब हाई बीपी का पता चला तो मैं तुरंत अस्पताल जाकर डॉक्टर से मिली और दवाईयां शुरु की । डॉक्टर के अनुसार हाई बीपी में दिल का दौरा भी पड़ सकता है लेकिन अब मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूं क्योंकि मुझे समय से इसका पता चल गया।

क्या कहती है पीएचएफआई

दूर दराज के में बसे गांव में आज भी लोगों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही। ऐसे में स्वास्थ्य स्लेट पब्लिक हैल्थ की दिशा में दूरदराज के लोगों के लिए एक वरदान से कम नहीं है । स्वास्थ्य स्लेट की खासियत है कि यह एक छोटे से बैग में आ जाती है और इसको आसानी से कही भी ले जा सकते है । इसके माध्यम से लोगों को उनके अपने गांव में ही प्रारंभिक जांच कर उन्हें तुरंत परामर्श दिया जा सकता है कि उनके शरीर में किस प्रकार की बीमारी आ गई है या आने की संभावनाएं है तथा विस्तृत जांच के लिए पंजीकृत लैबोरेटरी के लिए जाने की सलाह दी जा सकती है ।

डॉ. सुनील एस. राज
डीसीएच, एमडी,एमआरसीपी (यूके), एमपीएच
परियोजना प्रमुख

क्या कहते हैं विशेषज्ञ डॉ. के. आर. शांडिल

आज के भागमभाग और व्यस्त जीवन में लोगों के पास अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने का समय ही नहीं है हमारी जीवन शैली में हो रहे इस परिवर्तन से बीपी और शुगर जैसी समस्याओं में तीव्रता से इज़ाफा हो रहा है। इसके साथ ही हर आयु वर्ग के लोग तनाव का शिकार हो रहे है। न रात को सोने का समय न ही सुबह उठने का समय, अव्यवस्थित खान-पान, तनाव और चिंताग्रस्त दिनचर्या आदि मूल कारण है इन समस्याओं के पीछे । भागदौड़ की ज़िंदगी में यदि हम स्वयं के लिए समय नहीं दे सकते और हमें स्वास्थ्य के लिए आवश्यक जानकारियां नहीं पता है तो इससे भविष्य के लिए स्वास्थ्य के ख़तरे बढ़ जाऐंगें ।

स्वास्थ्य में आगे क्या

मिशन रीव के अंतर्गत हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर समस्या के पूरे तथा स्थाई समाधान की ओर बढ़ रहे हैं । प्रारम्भिक जांच के साथ-साथ लोगों को यह भी बताने का प्रयास है कि वह कैसे स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। स्वास्थ्य में हमारी अनूठी पहल शुरू हो रही है तथा जिन लोगों की जांच असामान्य पाई जाती है उन्हें मिशन द्वारा ही संचालित विस्तृत जांच के लिए सलाह दी जाती है । आज भी प्रदेश में कई गांव ऐसे है जहां से लोगों को अस्पतालों तक पहुंचने के लिए मीलों सफर तय करना पड़ता है। हमारी मोबाईल लैब मोटरसाईकिल पर गांव-गांव जाकर लोगों की विस्तृत जांच करती है जिसकी रिपोर्ट लैबोरेटरी विभागाध्यक्ष ऑनलाईन पुष्ट करते हैं। मरीज़ों से टेलिमेडिसन तकनीक से संवाद स्थापित किए जाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है तथा लोगों को सस्ती दवाऐं मिशन के अपने जेनेरिक मेडिसन ऑटलैट्स द्वारा घर द्वार पर प्रदान की जा रही है । एक निश्चित अवधि के बाद फॉलोअप भी शुरु होगा । इस प्रकार हम धीरे-धीरे इसमें फूडसप्लिमैंट व डाईट चार्ट की सुविधा भी जोड़ने वाले हैं ताकि स्वास्थ्य को लेकर सभी प्रकार की सेवाऐं घर-द्वार पर ही प्रदान कर सकें । यह इस दिशा में एक क्रांतिकारी क़दम साबित होगा तथा लोगों के स्वास्थ्य पर आने वाले खर्च को इस प्रयास द्वारा नियंत्रित किया जा सकेगा ।

पाठकों से अपील

प्रिय पाठक वर्ग

पाक्षिक विकासात्मक समाचार पत्र द रीव टाईम्स का प्रथम अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है । समाचार पत्रों में विकासात्मक गतिविधियों को समुचित स्थान मिलने से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का मूल उद्देश्य रहता है तथा विभिन्न नवीनतम एवं नवोन्वेशी कार्यों की प्रेरणा से विकास की तीव्रता को भी आधार मिलता है । विकास एंव आगे बढ़ने की तत्परता के बावजूद समयानुसार उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण सपनों को साकार करना सरल नहीं रह जाता है ।

द रीव टाइम्स लोगों को जीवन में प्रगतिशील बनने में कारगर सिद्ध हो, इसी उद्देश्य से आप की प्रतिक्रियाओं, आलोचनाओं, सुझावों तथा परामर्श को सादर आमंत्रित करते हैं ताकि विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने संबन्धि सभी पहलुओं का शनैः-शनैः समावेश किया जा सके ।

मिशन रीव के अंतर्गत जो विभिन्न प्रगतिशील कार्यक्रम आम जनता के लिए चलाए जा रहे हैं उनका समाज के सभी वर्गों को यथासंभव लाभ मिल सके ऐसे में द रीव टाइम्स से संभव होता दिखाई दे रहा है । आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित है ।

आनन्द नायर
प्रबन्ध संपादक द रीव टाइम्स

हर दिन नए आयाम

मिशन रीव अपने आरंभ से ही दिन-प्रतिदिन नए आयाम रच रहा है । इसी कड़ी में रीव अब पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नए रूप में सामने है जिसे पाठक अब द रीव टाइम्स प्रारूप में पढ़ पाएंगें और इस से हृद्य से जुड़ेंगें । मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है कि मिशन रीव इस क्षेत्र में भी अब जन-भावनाओं के साथ आगे बढ़ेगा तथा द रीव टाइम्स आमजन की आवाज़ बनेगा ।

प्रोफेसर आर.के. गुप्ता
चेयरमैन, आईआईआरडी

Message from Mission Head, Mission RIEV

It is a fortnight since I have been associated with Mission RIEV as its Head. If feel proud for my association with Mission RIEV, which has been designed to serve the population of their requirements at their door steps at nominal cost.

The Mission RIEV has been designed on 'Self Sustaining Economic Model'. Sincere efforts will be made to achieve the objectives of the Mission by increasing outreach and availability of services for all in a time bound manner.

Cooperation from all is solicited!

N K Sharma
Mission Head, RIEV

पांच जन औषधि केन्द इसी सप्ताह होगें शुरू

शिमला, टीम रीव

आईआईआरडी की ओर से प्रदेश में तीन सौ जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इसी कड़ी में पहले पांच केंद्रों का उदघाटन आईआईआरडी शिमला कार्यालय से किया जाएगा। इस मौके पर अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव बीके अग्रवाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। उन्हीं के द्वारा पांच जन औषधि केंद्रों का उदघाटन किया जाएगा। यह केंद्र मंडी, कांगड़ा और शिमला में खोले जा रहे हैं। इनमें कांगड़ा में दो , मंडी में दो और शिमला में एक केंद्र खोला जा रहा है। इन केंद्रो पर लोगों सस्ते दामों पर दवाईयां उपलब्ध रहेगी। पहले चरण में पांच केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इसी तरह प्रदेश के बाकि जिलों में भी केंद खोले जाएंगे।

मिशन रीव: एक सोच जो बदल देगी जीवन

जीवन संर्घष का दूसरा नाम है तथा हर व्यक्ति का संर्घष स्वयं में जटिल तथा चुनौतिपूर्ण है । चंद व्यक्ति अपने संर्घष तथा चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते है लेकिन अधिकांश इतने टूट जाते हैं कि दोबारा उठना मुश्किल हो जाता है । इसके अतिरिक्त जीवनयापन की इस यात्र में कुछ सरकारी तथा ग़ैर सरकारी कार्य ऐसे होते हैं जिनके बग़ैर आगे बढ़ना मुश्किल होता है तथा इन कार्यों को सिरे चढ़ाना बहुत जटिल है ।

मिशन रीव का जन्म एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में हुआ है जहां से विभिन्न परिवारों की दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा रहा है। इस मिशन की खूबी यह है कि एक ओर जहां लोगों के दु:ख दर्द उनके घर-द्वार पर दूर हो रहें हैं वहीं दूसरी ओर गांव में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए अपने जीवन-यापन के अवसर पैदा हुऐ हैं । हर पंचायत क्षेत्र में कम से कम तीन व्यक्तियों के प्रशिक्षित दल के साथ यह मिशन प्रदेश में लगभग 10,000 युवाओं को रोज़गार देने की प्रक्रिया में है जो कि यह संख्या आगे चलकर 50,000 तक पहुंच सकती है ।

यह मिशन बिना किसी सरकारी सहायता से शुरू किया गया, बस अपनी सेवाओं के सापेक्ष लाभार्थी अपना अंशदान देकर इस मिशन को सफल बनाने के लिए खड़े हो रहे हैं तथा इसकी व्यापकता के लिए एक बड़ा आई टी प्लेटफॉर्म/सॉफ्टवेयर की संरचना हो रही है । विभिन्न सरकारी तथा ग़ैर सरकारी निकायों से पार्टनरशिप हो रही है , ग्राम पंचायत , ब्लॉक, ज़िला तथा राज्य स्तर तक समाज के प्रभावी तबके को मिष्ठान का हिस्सा बनाया जा रहा है ।

यह मिशन हर व्यक्ति का मिशन बने, इसके लिए एक सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें अंतर्गत बनने वाले सदस्यों की व्यक्तिगत समस्याओं तथा आवश्यकताओं का भी आकलन किया जा रहा है ताकि उन सबके लिए उपयुक्त समाधान तथा सहायता प्रक्रिया तैयार की जा सके ।

सदस्यता अभियान

मिशन रीव के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए वार्षिक सदस्यता ग्रहण करने की व्यवस्था की गई है । जिसका वार्षिक शुल्क मात्र 2000 रू. है । मिशन मे पंजीकृत परिवार के सभी सदस्यो को वार्षिक स्वास्थ्य समृद्धि चार्ट सहित उपलब्ध सेवाओं के लागत मूल्यो में 25 से 50 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जा रही है ।

क्यों बने सदस्य -

-हमारी टीम, आपको मिशन रीव के सदस्य बनने पर आपकी की जरूरतों की पहचान करेगी। इसके पश्चात आपकी जरूरतों एवं समस्याओ की चरणबद्ध तरीके से सूची बनाकर आपकी जरूरतों के मुताबिक सेवाएं एवं समाधान प्रदान करेंगी ।

उदाहरण के लिए, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है और ईलाज करने मे परेशानी आ रही है तो हमारा पंचायत फेसिलिटेटर आपके घर पर आकर आपके स्वास्थ्य की जांच सम्बन्धि विभिन्न प्रकार के टेस्ट मोबाईल लेबोरेटरी के द्वारा करवाने मे तथा डाक्टरों/स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ जोड़ने में सहयोग प्रदान करेगा । इतना ही नहीं वह भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत उपलब्ध सस्ती सरकारी दवाईयां भी आपके घर पर पहुंचाने मे सहयोग करेगा ।

सदस्य के विशेषाधिकार

1- सदस्य के पास करीब 40 प्रकार की सेवाएं निशुल्क प्राप्त करने का विशेषाधिकार रहेगा ।

2- एक सदस्य को वार्षिक स्वस्थ्य चार्ट निशुल्क प्रदान किया जायेगा ।

3- मिशन रीव के पंचायत फेसिलिटेटर सदस्य के घर द्वार जाकर 'आवश्यकता आकलन' करेंगे ।

4- सभी महत्वपूर्ण एवं आय वर्धक अवसर सहित नई योजनाओं की जानकारी एस. एम. एस. या अन्य तरीकों से मात्र सदस्यों से ही साँझा की जाएगी ।

5- गैर सदस्यों की अपेक्षा सदस्यों की चिन्हित समस्याओं का समाधाान प्राथमिकता के आधाार पर प्रदान किया जायेगा ।

6- सदस्यों को सभी तरह की सेवाएं निर्धारित मूल्य की अपेक्षा कम मूल्य पर उपलब्ध होंगी ।

कैसे मिलेगी सुविधाएं-

मिशन रीव का सदस्य बनने के लिए आप हमारे पंचायत फैसिलिटेटर से सम्पर्क कर सशुल्क सदस्यता फार्म भरवाकर अपनी सदस्यता सुनिश्चित कर सकते है। एक बार सदस्य बनने के बाद आपकों अपनी जरूरतो एवं समस्याओ को पंचायत फेसिलिटेटर के साथ साझा कर एक सूचि तैयार करनी होगी, इसी सूची के माध्यम से हम आपकी हर समस्या एवं जरूरत का समाधान खोजने मे आपके घर-द्वार पर आकर आपकी यथासंभव मदत करेगें।

शिकायत निवारण प्रक्रिया

अगर आपको पंचायत फेसिलिटेटर द्वारा दी गई सेवाओ से सम्बन्धित कोई शिकायत है तो इसकी सूचना आप हमारे ब्लॉक कोआर्डिनेटर को दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे जिला व स्टेट कोआर्डिनेटर और मुख्य कार्यालय में फोन अथवा ई मेल के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं।

यह सभी जानकारी हमारी वेबसाइट www.missionriev.in पर उपलब्ध है।

RIEV: Shifting Rural Growth From A Canter to A Gallop...

Fourteen years back, in Shimla, a small NGO started its journey with a cantor. At that time, no one imagined that this canter would turn into a gallop and NGO into a behemoth named IIRD. Through a vast concept of Mission RIEV, IIRD actually trailed a blaze for rural development in hilly state Himachal.

The terrain of Himachal is thwarting our youth to fulfill their ambitions. Albeit, there are many government schemes for the upliftment of rural areas, still, meager information and many technological obsolescence bereft of rural's growth opportunities.

To bridge this yawning gap IIRD launched Mission RIEV in the year 2017. Under this sui generis Mission, IIRD is covering Health, Agriculture, Sanitation, Environment, Conservation of Natural Resources, Skill Development, Education, Online Services & whole shebang related to development in rustic milieu.

On 26th Feb, 2018 a new chapter was added to the history of hill state development when Hon'ble Minister for Rural Development & Panchayti Raj Mr. Virender Kanwar launched the services under mission RIEV. The event organised at IIRD Complex saw august gathering of Minsters, Secretaries of the state and other guests.

IIRD Chairman Mr. R.K. Gupta addressed the gathering through his welcome speech.

Dr. L.C Sharma- MD, IIRD gave a presentation on Development Vision of Himachal Pradesh. The presentation highlighted different aspects of development related to Education, Skill Development, Health, Sanitation, Eco-Tourism, Employment, Entrepreneurship and Infrastructure.

Addressing the gathering Chief guest, Hon'ble Minister for Rural Development Mr. Kanwar appreciated the Mission RIEV initiatives. He spoke about present social issues like employment, environment degradation, education, public health and others. Talking about the present scenario and Mission RIEV initiatives in the field of Rural Development, he assured his full support to Mission RIEV. He was overwhelmed by the innovative technology introduced by Mission RIEV such as Path labs for medical tests and RIEV Organics.

IIRD under Mission RIEV has recently flagged off four RIEV Clinic Path Bikes. These mobile lab provide 72 Test at affordable price . Swasthya Slate is another gem, added to health project under Mission RIEV. It is a Bluetooth enabled integrated diagnostic kit that works on android based mobile system and is able to perform 30 plus tests. Recently these services have been started in various district of Himachal Pradesh and people in rural areas are getting health benefit.

Anjna Thakur
Associate Editor

अब रक्त जांच की सुविधा घर द्वार पर

दो माह में तीन हजार लोगों के स्वास्थ्य की जांच

रामपुर के शोली में ग्रामिणों का स्वास्थ्य जांच करने पहुंची मिशन रीव की टीम

शिमला, टीम रीव

आईआईआरडी शिमला की ओर मिशन रीव के तहत प्रदेश के उन क्षेत्रों मे स्वास्थ्य सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है जहां आसानी से आमतौर पर अन्य संस्थाएं नही पहुंच पाती। मिशन रीव के तहत शिमला के चौपाल, कुपवी, रोहडू समेत अन्य दूरदराज के क्षेत्रें में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसकी पहली कड़ी में घर द्वार पर टेस्ट की सुविधा बाजार से बेहद कम दामों पर उपलब्ध कराई जा रही है।

पिछले महज दो माह के भीतर जिला शिमला में ही दो हजार से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उनके घरद्वार पर ही उपलब्ध करवाई गई।

इस दौरान शिमला के विकासनगर, ऑकलैंड, आईआईआरडी शिमला, ठियोग, शोली, रामपुर, रोहडू, छवारा, मूलकोटी, जुब्बल, आईआईआरडी के इस प्रयास की प्रशंसा भी ग्रामीण क्षेत्रों मे खूब की जा रही है।

रीव क्लीनिक मोबाईल पैथ लैब के एचओडी डाक्टर के.आर. शांडिल ने बताया कि इस शिविर में मोबाइल बाइक लैब से एक हजार से अधिक लोगों के रक्त की जांच की जा चुकी है।

70 से अधिक टेस्ट एक साथ कराने की है सुविधा

इनमें मिशन रीव के सदस्यों को निशुल्क सेवाएं दी गई। इसके लिए आईआईआरडी शिमला कार्यालय में लैब तकनिकी सहायक को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।

आम लोगों तक जैनरिक दवाएं पहुंचाएगा आई.आई.आर.डी.

शिमला, टीम रीव

जनऔषधि दवाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों से सीधी बात की गई। इस मौके पर आईआईआरडी शिमला में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस मौके पर आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डाक्टर एलसी शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना के तहत हिमाचल प्रदेश मिशन रीव के माध्यम से तीन सौ जनऔषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और विभिन्न स्थानों पर केंद्र खोले जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि मिशन के तहत गांवों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही विभिन्न प्रकार की तकनीकी सेवाएं घर द्वार पर उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिनके लिए सामान्य लोगों को महीनों शहरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इन सेवाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, बैकिंग, सरकारी योजनाओं के आवेदनों सहित कई प्रकार की सेवाएं शामिल हैं, जो लोगों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हैं।

एमडी डॉ. एल.सी. शर्मा के अनुसार ग्रामीण भारत को विकास की तीव्रता प्रदान करने के लिए ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए त्वरित सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता है।

जैविक राज्य का सपना साकार कर रहा आईआईआरडी का मिशन रीव

गांवों में जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण देते मिशन रीव के प्रतिनिधि

शिमला, टीम रीव

सिक्किम की तर्ज पर हिमाचल को जैविक राज्य बनाने के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान शिमला आईआईआरडी अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। हिमाचल को जैविक राज्य बनाने के लिए आईआईआरडी मिशन रीव के तहत प्रदेश के गांवों में किसानों और बागवानों को जैविक खाद बनाने का निशुल्क प्रशिक्षण दे रहा है। इतना ही नही किसानों को जैविक खाद बिक्री के लिए बाजार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है।

यह पहली बार है कि कोई संस्था गांव के लोगों को उन्हीं के घरद्वार पर रोजगार के साथ साथ व्यवसाय शुरू करने का भी अवसर प्रदान कर रही है। इस काम को सिरे चढ़ाने के लिए आईआईआरडी की ओर से मिशन रीव के तहत पंचायतों में अपने प्रतिनिधियों की तैनाती की गई है। संस्था के ये प्रतिनिधि गांवों में ही किसानों और बागवानों को जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं।

इन प्रतिनिधियों को आईआईआरडी शिमला में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। संस्था के इस प्रयास की ग्रामीण क्षेत्रें में काफी सराहना हो रही है। लोगों का कहना है कि खाद बनाना तो आसान है पर उसकी बिक्री अभी तक मुश्किल थी लेकिन आईआईआरडी ने इसे आसान बना दिया है।

प्रशिक्षण के साथ बिक्री के लिए बाजार भी

आईआईआरडी के प्रबंधक निदेशक डाक्टर एल.सी. शर्मा का कहना है कि हिमाचल का विकास तभी संभव है जब गांव के लोगों के पास रोजगार और व्यवसाय के अवसर होंगे। जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण देकर गांव के लोगों को व्यवसाय का भी अवसर दिया जा रहा है।

योगा डे पर एक साथ किया योगा

शिमला, टीम रीव

अंतर्राष्ट्रीय योगा डे यानि बीते 21 जून को आईआईआरडी शिमला में विशेष तौर पर योगा डे का आयोजन किया गया। इस मौके पर आईआईआरडी, हिंद सेवा संगठन, "फ्लायर ग्रुप, मिशन रीव तथा आईआईआरडी से जुड़े विभिन्न सदस्यों ने एक साथ योगा आसन किए। इस मौके पर आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डाक्टर एलसी शर्मा, हिंद सेवा संगठन की निदेशक सुषमा शर्मा, को डायरेक्टर एस.के. शर्मा, "फ्लायर ग्रुप" के निदेशक आनंद नायर, प्रोजैक्ट हैड आर.के. सिंह, लैब हैड डा. केआर शांडिल समेत आईआईआरडी के अन्य स्टाफ सदस्यों ने योगाआसन किए।

लंबी दाड़ी वाले बाबा ने जमकर हंसाया

तनाव दूर करने के लिए एचआर ने किया आयोजन

तनाव दूर करने के लिए प्रस्तुति देते आईआईआरडी के सदस्य

शिमला, टीम रीव

दिन भर काम के बाद की थकान को मिटाने और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए आईआईआरडी शिमला में एचआर विभाग की ओर इस अनूठे आयोजन की शुरुआत की गई।

इसके तहत हर माह के आखरी दिन एक मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एचआर अधिकारी राघव भारद्वाज ने बेहद मनोरंजक प्रस्तुति दी। राघव की ओर से लंबी दाड़ी वाले बाबा ऐसी खीर बनाएंगे..., पर जहां आईआईआरडी सदस्यों को नचाया गया वहीं सबको हंस हंस कर लोट-पोट होने के लिए भी राघव की प्रस्तुति ने मजबूर कर दिया। एचआरओ राघव ने बताया कि अब हर माह की अंतिम तारीख को इस तरह का आयोजन किया जाएगा।

द रीव टाइम्स
रूरलाइजिंगं इंडिया इंपावरिंग विलेजिज़

मानसिक तनाव से बचने के लिए एनएलपी सेशन

एसजेवीएनएल शिमला में फ्लायर ग्रुप की ओर से आयोजित एनएलपी सेशन

शिमला, टीम रीव

आईआईआरडी के तहत फ्लायर ग्रुप की ओर से एसजेवीएनएल शिमला और रामपुर में एनएलपी सेशन का आयोजन किया गया। फ्लायर ग्रुप के निदेशक व सी.ई.ओ. की अध्यक्षता मे आयोजित इस सेशन में व्यस्त और मानसिक दबाव से भरे जीवन में सकारात्मक सोच के के वैज्ञानिक महत्व में बारे में जानकारी दी।

फ्लायर ग्रुप के सीईओ आनंद नायर का कहना है कि आज के दौर में व्यस्तताएं इतनी अधिक है कि मनुष्य न चाहते हुए भी तनाव में आ जाता है। ऐसे में एनएलपी कार्यक्रम तनाव को दूर करने के साथ ही कार्यक्षमता को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं।

एसजेवीएनएल के वरिष्ठ अधिकारियों बिजय प्रसाद और अनुराग भारद्वाज ने भी आईआईआरडी की ओर से आयोजित किए जाने वाले इस तरह के कार्यक्रमों को संस्थागत प्रोत्साहन के लिए काफी

देश के पहले मतदाता भी जुड़े हैं मिशन रीव से

किन्नौर, टीम रीव

देश के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी भी मिशन रीव से जुड़े हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय मिशन रीव में ग्रामीण विकास एवं आमजन उत्थान के तहत उस समय एक ऐतिहासिक कदम जुड़ गया जब भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी ने किन्नौर में मिशन रीव की सदस्यता ग्रहण की। मिशन के जिला किन्नौर के कोआर्डिनेटर विशाल नेगी और ब्लॉक कोआर्डिनेटर द्वारा उनकी सदस्यता करवाई गई।

मिशन रीव ने उठाया स्वास्थ्य देखभाल का जिम्मा

मिशन रीव के तहत सदस्यता अभियान पूरे हिमाचल में चलाया जा रहा है और इसकी सदस्यता लेने वाले नागरिक को संस्थान के द्वारा आम सुविधाओं को उनके घर तक पहुंचाया जाता है।

रीव के सदस्य होने के नाते आईआईआरडी ने देश के पहले मतदाता को विभिन्न सेवाएं जैसे समय समय पर उनकी स्वास्थ्य जांच व अन्य दस्तावेजी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी ली है। श्री नेगी का कहना है मिशन रीव जैसे अभियान प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोंगों के लिए कफी लाभदायक साबित होंगे। मिशन रीव के संस्थापक डॉ. एल सी शर्मा ने बताया कि श्याम सरन नेगी ने इस मिशन की प्रशंसा की। नेगी ने कहा कि अभी भी गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी है और प्रशासन की ओर से गांव के विकास के लिए कोई सशक्त कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन अब मिशन रीव से इस गांव की उम्मीदें बंधी हैं और सभी गांववासियों को इससे जुड़ना चाहिए।

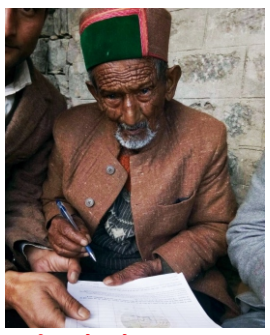

मिशन रीव की सदस्यता ग्रहण करते हुए श्याम सरन नेगी

लाहौल-स्पीति में सफलता के सफर की शुरुआत

लाहौल-स्पीति, टीम रीव

आईआईआरडी ने अपने बहु आयामी प्रोजेक्ट मिशन रीव को जिला लाहुल-स्पीति के केलांग ब्लाक में सफलता पूर्वक आरंभ करने के बाद स्पीति में भी प्रशिक्षण शिविर लगा कर शुभारंभ कर दिया।

इस मौके पर राज्य समन्वयक सुरेंद्र देओल व जिला समन्वयक विशाल नेगी ने स्पीति के मशहूर कीह गोंपा मठ के अधिकारी नीमा लामा तथा पंगमो मठ के अधिकारियों से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया।

प्रशिक्षण शिविर से युवाओं में जोश

कीह मठ के अधिकारी नीमा लामा को जानकारी देते हुए मिशन रीव के अधिकारियों ने बताया कि मिशन रीव के माध्यम से स्पीति में जैविक खेती, सोलर एनर्जी, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अर्थात निवारक स्वास्थ्य सेवाओं, जल संरक्षण जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं और जरूरतों के क्षेत्र में कार्य किए जाएंगे। कीह मठ में नीमा लामा जी ने अपने व्यस्तम

केलागं में मिशन रीव के पंचायत कार्यलाय का शुभारम्भ करते मिशन प्रतिनिधि

दिनचर्या में से लगभग एक घंटे का समय देकर स्पीति घाटी की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की तथा मिशन रीव द्वारा जन सरोकार के इन क्षेत्रें में काम किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मिशन रीव की शुभकामनाएं दी और संपूर्ण सहयोग देने का आज्वासन दिया। इस प्रशिक्षण शिविर में, दैमुल, लालुंग, हल, किब्बर तथा संगनम आदि पंचायतों के नौजवान युवक युवतियों छेरग अंगरूप, तंडुप छैंरग, नीमा डोलमा, तंडुप अंगियाल, तेनजिन तंडुप तथा तेनजिन छोड़ोन आदि ने प्रशिक्षण लेकर मिशन रीव को सफल बनाने का बीड़ा उठाया है।

सरकार और आम आदमी के बीच खाई पाट रहा रीव

सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का बना सहारा

विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाते मिशन रीव के प्रतिनिधी

ऊना, टीम रीव

जानकारी और दस्तावेजी पेचिदगियों के चलते अक्सर सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों को नहीं मिल पाता जिन लोगों के लिए ये योजनाएं बनाई जाती है। ऐसे में न तो सरकार अपने लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त कर पाती है और न ही लोगों को योजनाओं का लाभ मिल पाता है। समाज कल्याण की राह में रोड़ा बन रही इन समस्याओं का निवारण करने में आईआईआरडी का मिशन रीव अहम भूमिका निभा रहा है। दरअसल रीव सरकार और आम जनता के बीच खाई को पाटने में एक मजबूत कड़ी बनता जा रहा है। जिला ऊना में मिशन रीव के तहत ऐसे कई उदाहरण है।

जिला ऊना गगरेट ब्लॉक में गगलेहर गांव के निवासी चानन सिंह के मुताबिक जब उन्होंने मिशन रीव की सदस्यता ली थी तो उन्हें शुरूआत में विश्वास नहीं हुआ कि उन्हें सही में एक साथ इतनी सेवाएं मिलेगी। लेकिन अब मिशन रीव के सदस्य के तौर पर वह 15 से अधिक सेवाएं ले चुके हैं। चानन के मुताबिक मिशन रीव से उनके जीवन की राह आसान हो गई है। ऊना के जिला समन्वयक हनीश का कहना है कि चानन सिंह को सबसे पहले बैंक से लोन दिलवाने में उनकी टीम ने मदद की। उसके बाद घर बनाने के लिए श्रमिक, निशुल्क स्वास्थ्य जांच, जीएसटी नंबर, जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण, राशन कार्ड में नाम जोड़ने, कार लेने, बीएसएनएल का क्नेक्शन दिलाने, बाइक, कार और घर का इंशोरेंस करने और उनके व्यवसाय को आगे ले जाने में मिशन रीव ने चानन के परिवार की पूरी सहायता की और वह रीव से काफी खुश है।

चानन की तरह ऊना में मिशन रीव कई लोगों के जीवन की राह आसान करने में जुटा है।

हैल्थ कैंप में तीन सौ से अधिक का स्वास्थ्य जांचा

गांव में ही टेस्ट सुविधा मिलने से ग्रामीण खुश

सोलन, टीम रीव

लोगों को उनके घरद्वार पर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उद्देश्य से मिशन रीव के तहत अभी तक करीब 15 स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। इनमें जहां सदस्यों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच की जा रही है वहीं अन्य लोग भी इस सेवा का लाभ ले रहे है। गांव में ही टेस्ट की सुविधा मिलने से ग्रामिणों में भी खुशी की लहर है। सोलन ब्लॉक के माझीवर पंचायत के बाशिंदों कहना है कि पहले उन्हें ब्लड प्रेशर तक की जांच के लिए शहर जाना पड़ता था लेकिन अब गांव में ही विभिन्न तरह के टेस्ट की सुविधा है। इसके चलते स्वास्थ्य का ध्यान और समय समय पर

ब्लड टेस्ट कराने में आसानी हो गई है। माझीवर पंचायत की ही तर्ज पर कंडाघाट ब्लॉक की बीज़ा पंचायत, कुनिहार ब्लॉक चखेर पंचायत समेत विभिन्न स्थानों पर इस तरह के स्वास्थ्य शिविरों में लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है।

मदनपुर में खुला ब्लॉक कार्यालय

कार्यालय में मिशन रीव के सदस्य

ऊना, टीम रीव

लोंगों को मिशन रीव के तहत सेवाएं लेने में परेशानी न हो इसके लिए पूर प्रदेश में जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर तक कार्यालय खोले जा रहे हैं। इसी कड़ी में ऊना ब्लॉक कार्यालय मदनपुर में खोला गया है।

इस कार्यालय में लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला समन्वयक हनीश, ब्लॉक समन्वयक गुरूमुख, पंचायत फेसिलिटेटर परमजीत कौर, हरजीत कौर, जय गोपाल व अन्य सदस्यों ने सहयोग दिया।

प्रशिक्षण से कौशल में आ रहा निखार

ऊना, टीम रीव

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्थानों पर किसानों को आईआईआरडी की ओर से मिशन रीव के तहत निशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत कलोह, बसोली पंचायत तथा अन्य कई स्थानों प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके

ऊना में ग्रामिणों को जैविक खेती के बारे में जानकारी देती मिशन रीव की टीम

अलावा कृषि विभाग की उन सेवाओं के बारे में भी इन किसानों को अवगत कराया जा रहा है जिसका लाभ वे सरकारी तौर पर उठा सकते हैं। इन योजनाओं का लाभ लेने में भी मिशन रीव के सदस्य गांवों के लोगों का भरपूर सहयोग कर रहे हैं ।

जैविक खाद बनाने का दिया प्रशिक्षण आसान हुई जैविक खेती की राह

प्रशिक्षण के बाद ग्रामीणों द्वारा तैयार की गई जैविक खाद बाज़ार में बिकने के लिए तैयार

सिरमौर, टीम रीव

मिशन रीव के तहत सोलन की विभिन्न पंचायतों में जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण मिशन रीव के तहत दिया जा रहा है। इतना ही नहीं अगर कोई जैविक खाद बनाकर उसकी बिक्री करना चाहता है तो आईआईआरडी की ओर से उसे वह खाद खरीद कर मुनाफा कमाने का अवसर भी दिया जा रहा है। अभी तक अकेले जिला सिरमौर की ही विभिन्न पंचायतों में ही दो सौ से अधिक किसानों को जैविक खाद बनाने का निशुल्क प्रशिक्षण मिशन रीव के तहत लोगों को दिया जा रहा है। राजगढ़ और सगड़ाह में लोग मिशन रीव के इस प्रयास से काफी खुश है। स्थानीय लोगों भीम सिंह, ध्यान सिंह, नैन सिंह व अन्य लोगों का कहना है कि उन्होंने अभी तक जैविक खाद के बारे में कई बार सुना था लेकिन यह कैसे बनती है इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। मिशन रीव के प्रतिनिधियों ने गांव के लोगों को इसका निशुल्क प्रशिक्षण देकर बेहतरीन कार्य किया है।

निशुल्क प्रशिक्षण से सैंकड़ों किसानों को लाभ

इसका सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि लोगों को प्रशिक्षण लेने के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा और न ही सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ेंगे। अगर कुछ पूछना हो तो आईआईआरडी के पंचायत फेसिलिटेटर अपनी ही पंचायत में उपलब्ध हैं जो तुरंत सेवा प्रदान करने को तैयार रहते हैं।

अब आसान हुई फसलों और बागीचों की देखभाल

मिशन रीव के तहत किसानों तक पहुंचे स्प्रे पंप

सोलन, टीम रीव

सरकार ने किसानों के लिए सोलर स्प्रे पंप पहुंचाने की व्यवस्था तो कर दी लेकिन किसानों तक वह कैसे पहुंचे इसके लिए कोई स्टीक योजना धरातल पर नहीं है। ऐसे में आईआईआरडी का मिशन रीव किसानों के लिए मार्गदर्शक के तौर पर उभरा हैं। मिशन के सदस्य जहां किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं वहीं इन योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने में भरपूर मदद कर रहे हैं। जिला सोलन में इसके कई जीवंत उदाहरण हैं। इनमें से एक है सोलर स्प्रे पंप मशीवर पंचायत के दिनेश का कहना है कि पहले ज्यों ही स्प्रे करने का सीजन आता था त्यों ही हम सोच में पड़ जाते थे कि साधारण पंप से सही स्प्रे कैसे करें। फिर सरकारी पंप के बारे में सुना लेकिन पंप कैसे और कहां से मिलेगा, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद

मिशन रीव के प्रतिनिधियों ने योजना की पूरी जानकारी दी। इतना ही नहीं पंप घर तक पहुंचा दिया गया।

दिनेश की तरह ही जिला सोलन की विभिन्न पंचायतों में कई किसान और बागवान है जो रीव सोलर स्प्रे पंप से अपनी फसलों और बगीचों की देखभाल कर रहे हैं।

सोलर लाइट से होते हैं चार्ज

सोलन के निवासी देवी राम, रीता, श्यामा का कहना है कि मिशन रीव ने उन्हें पंप दिलाकर उनका काम आसान कर दिया। पहले साधारण पंप से उन्हें स्प्रे करने के लिए कफी मुश्किल होती थी। इसको पहले कई घंटो तक बिजली से चार्ज करना पड़ता था और बिजली न होने की स्थिति में यह काम नहीं करता था ।

कांगड़ा के विकास को गति प्रदान कर रहा है मिशन रीव

मिशन रीव के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करते आईआईआरडी के विशेषज्ञ

कांगड़ा, टीम रीव

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में मिशन रीव विभिन्न माध्यमों से सेवाओं को आमजन तक पहुंचा रही है । ज़िला कांगड़ा की 1654 पंचायतों में पंचायत फेसिलिटेटर अपनी सेवाऐं गांव के लोगों को दे रहे हैं, जिसमें 215 से अधिक फेसिलिटेटर शामिल हैं । लोगों के रोजमर्रा के जीवन में आने वाली सामान्य समस्याओं के समाधान के अतिरिक्त मिशन रीव के कार्यकर्त्ता उन दुर्गम क्षेत्रों में भी लोगों तक पहुंच रहे हैं, जहां पहुंच पाना बहुत ही कठिन है । मौजूदा समय में मिशन कार्यकर्त्ता स्वास्थ्य सेवाऐं लोगों को घर-द्वार पर ही उपलब्ध करवा रहे हैं । स्वास्थ्य स्लेट के माध्यम से विभिन्न तरह की स्वास्थ्य जांच घर-द्वार ही उपलब्ध करवाई जा रही है । इसके अतिरिक्त जैविक खेती व जैविक खाद के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि आम आदमी को यूरिया इत्यादि जैविक खादों की सही जानकारी व उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके ।

ज़िला की अलग-अलग पंचायतों में परिवारों की आवश्यकताओं का आकलन किया जा रहा है तथा उनके अनुसार ही सेवाऐं प्रदान की जा रही है । आई.आई.आर.डी. के दिशा निर्देशों में लोगों के जीवन को सरल एवं सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विगत छः माह में रीव ने बेहतरीन करते हुए विभिन्न पंचायतों में 350 से अधिक हि.प्र. यूनिवर्सल हैल्थ कार्ड मुहैया करवाए गए, बी पी एल परिवारों को इंदिरा आवास योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाने के लिए मिलने वाले अनुदान में सहायता की गई । पूरे ज़िला में 650 से अधिक लोगों के घर-द्वार पर ही पैन कार्ड बनाए गए । इसके अलावा 200 से अधिक लोगों के आधार कार्ड पंचायत स्तर पर ही संशोधित किए गए, वृद्धों एवं विधवाओं को पेंशन लगाने में सहायता की गई ताकि सरकार की योजनाऐं लोगों को सुलभ हो सकें । घर-द्वार पर ही लोगों के विभिन्न प्रकार के टैस्ट सुनिश्चित किए जा रहे हैं जिनके लिए पहले लोगों को दूर-दूर तक जाना पड़ता था । जो पंचायतें अभी रीव की सेवाओं से वंचित है उनको भविष्य में स्वालंबी बनाने और सेवाओं से जोड़ने के उद्देश्य से मिशन रीव पंचायत स्तर पर फैसिलिटेटर की भर्ती करेगा ।

जिला कांगड़ा में मिशन रीव की टीम

- यूनिवर्सल हैल्थ कार्ड सेवाऐं
- पंचायत एवं सरकार की योजनाओं की जानकारी
- आवास योजनाओं की जानकारी व उपलब्धता
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड बनाने की सुविधा
- प्रशिक्षण आदि सेवाऐं जहां पहुंच पाना बहुत ही कठिन है ।

हमीरपुर में रीव ने उठाया ग्रामीणों के स्वास्थ्य का जिम्मा

लोगों को घर पर ही मिल रही स्वास्थ्य जांच की सुविधा

हमीरपुर, टीम रीव

हमीरपुर ज़िला में मिशन रीव द्वारा विभिन्न माध्यमों से सेवाऐं प्रदान की जा रही है । अपने आगाज़ के साथ ही मिशन रीव की पूरी टीम हमीरपुर में गांव-गांव जाकर आमजन से जुड़ने के लिए प्रयासरत है । हमीरपुर में स्वास्थ्य स्लेट का कार्य मिशन रीव द्वारा चलाया जा रहा है । इसमें लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है । हमीरपुर के सुजानपुर में मिशन रीव के तहत स्वास्थ्य स्लेट का कार्य किया गया जिसमें सैंकड़ों लोगों ने भाग लिया तथा लाभान्वित हुए । इसे निरंतर जारी किया गया है तथा अलग-अलग स्थानों पर लगाया जा रहा है

हमीरपुर ज़िला में सर्वप्रथम सदस्यता अभियान चलाया गया । लोगों को जोड़ने के बाद उनकी आवश्यकताओं की सूची तैयार की गई और उसी आधार पर सेवाऐं प्रदान की जा रही है । लोगों के साथ गांव में बैठक आयोजित की जा रही है तथा उनकी समस्याओं में मिशन रीव साथी बना है । सुजानपुर खण्ड की स्पाहल पंचायत में लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविर व स्वास्थ्य स्लेट का आयोजन किया गया जिसमें लोगों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया । इसके साथ ही आसपास की पंचायतों के लोग भी लाभान्वित हुए । लोगों ने घर-द्वार पर मिल रही सुविधाओं के लिए मिशन रीव को सराहा है ।

- स्वास्थ्य स्लेट के अंतर्गत लोगों को सेवाऐं प्रदान की गई
- सुजानपुर एवं आसपास की पंचायतों में नियमित

मिशन रीव से आसान हुआ गांवों का जीवन

घर-घर मिल रही सेवा

जैविक प्रशिक्षण एवं टब प्रदान करती मिशन रीव की टीम

हमीरपुर, टीम रीव

हमीरपुर के बिझड़ी में लोगों ने कृषि विकास के लिए योजनाएं तो बनाई लेकिन इन योजनाओं को पूरा करने का जरिया उनके पास नहीं था। कृषि में प्रयोग होने वाले विभिन्न उपकरणों को कहां और कैसे प्राप्त किया जाए, इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

लोगों की इसी समस्या को दूर करने के लिए मिज़न रीव के तहत लोगों की जरूरतों को पहचाना गया बल्कि उनकी जरूरतों को पूरा भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में इसके लिए मिशन रीव के तहत पंचायत में तैनात आईआईआरडी के प्रतिनिधि विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

हाल ही में बिझड़ी ब्लॉक में पानी के 90 लीटर टबों का वितरण किया गया। यह टब बाजार से बेहद कम दाम पर लोगों के घरों तक पहुंचाए गए। मिज़न रीव के इस प्रयास की ग्रामीणों की ओर से भी खूब प्रज़ंसा की जा रही। रीता देवी, बालक राम व अन्य ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले ऐसा कोई नहीं था तो घर तक आकर जरूरत का सामान पहुंचाकर दे। लेकिन अब मिशन रीव के तहत यह काम किया जा रहा है जिससे गांव का जीवन भी आसान हो गया है। अपने स्तर पर सुविधाएं देने के अलावा मिशन रीव के तहत सरकारी योजनाओं की जानकारी और उन योजनाओं का लाभ कैसे उठाया जा सकता है इस बारे में भी मिशन रीव के तहत लोगों को अवगत करवाया जा रहा है।

बिलासपुर में जन-जन तक पहुंच रहा है मिशन रीव

बिलासपुर, टीम रीव

बिलासपुर में मिशन रीव लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतर रहा है तथा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सेवाओं को प्रदान किया जा रहा है । मिशन रीव ने टीम के साथ घर-घर जाकर लोगों की आवश्यकताओं का आकलन किया तथा सेवाओं के प्रति जागरुक भी किया । फेसिलिटेटर द्वारा विभिन्न पंचायतों में टीम रीव के साथ पेंशन फॉर्म भरने व अन्य औपचारिकताओं को पूरा करते हुए लाभार्थियों को पेंशन लगवाई भी गई । ग्रामीण लोगों को पैन कार्ड की सुविधाओं से अवगत करवा कर इसे बनाने में सहायता की । साथ ही यह प्रक्रिया सदस्यता से लेकर सेवाओं तक जारी है । मिशन रीव ने लोगों को मीटर लगाने की भी सेवाऐं प्रदान की । साथ ही लोगों को टब की उपलब्धता करवा कर इसे लोगों में वितरित किया गया । लोगों के घर-घर जाकर सभी लोगों से जानकारी लेकर उनका सर्वे करवाया तथा लोगों की मांग को जानकर सेवाऐं प्रदान की जा रही है । लोगों ने बेहतर गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाने के लिए मांग की जिसे रीव के तहत हरसंभव पूरा करने के लिए कार्य किया जा रहा है । इसी के तहत अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध करवाए गए हैं तथा उत्तम किस्म के पौधो भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जिनमें लीची, आम, अमरुद, सेब, मौसमी, नीम इत्यादि पौधो शामिल है ।

लोगों की आवश्यकताओं की जानकारी हेतु व्यापक पैमाने पर सर्वे किया जा रहा है तथा सर्वे को आधाार बनाकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टीम रीव तत्पर है ।

अपनी ही पंचायत में रोजागर मिलने से युवाओं में खुशी की लहर

बिलासपुर, टीम रीव

आईआईआरडी की ओर से प्रदेश में हर पंचायत में पंचायत फेसिलिटेटर की नियुक्ति की गई है। इसी तरह जिला बिलासपुर में भी विभिन्न पंचायतों में युवाओं को रोजगार का मौका मिशन रीव के तहत दिया गया है। अपनी ही पंचायत में रोजगार का मौका मिलने से युवाओं में खुशी की लहर हैं । मिशन रीव के तहत जो नियुक्तियां की गई है उसमें पंचायत फेसिलिटेटर की नियुक्ति संबंधित पंचायत से ही की गई है। ऐसे में युवाओं को अपने ही घर के पास रोजगार का मौका मिला है। इसके साथ वह अपनी पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों को भी मिज़न रीव के माधयम से पूरा कर हैं। लोगों के घरों में जाकर उनसे उनकी जरूरतें पूछी जा रही है और जरूरतों के मुताबिक सेवाएं भी प्रदान की जा रही है। लोगों का कहना है कि संस्था के प्रयास काफी सराहनीय है।

चंबा में रोजगार मुहैया करवा रहा है मिशन रीव

चम्बा में ग्रामिणों का स्वास्थ्य जांच करने पहुंची मिशन रीव की टीम

चम्बा, टीम रीव

चंबा ज़िले में मिशन रीव के तहत वृहद् जन कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर सेवाऐं प्रदान की जा रही है। ज़िले के लगभग 390 ग्रामीण युवा बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है तथा वे सभी ग्रामीण स्तर, खण्ड स्तर एवं ज़िला स्तर पर अपनी सेवाऐं प्रदान कर रहे हैं। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ज़िला में विभिन्न पंचायतों में जैविक खाद निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया। इससे किसानों में रासायनिक खाद को छोड़कर जैविक खाद बनाने व उपयोग करने की प्रक्रिया को अपनाने के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ी है। खण्ड तीसा एवं सलूनी में पंचायत फेसिलिटेटर ने पंचायत से संपर्क कर गांव-गांव जाकर लोगों से सीधा संपर्क साधा तथा उनकी समस्याओं को जाना। लोगों की मांग पर कम कीमत में फूलों का बीज, मटर तथा मक्की का बीज लागों को उनके घर पर ही प्रदान किया गया। खण्ड तीसा में अन्न भण्डारण के लिए ड्रम भी वितरित किए गए।

ऑनलाइन सेवाओं के बारे में आम ग्रामीणों को निरंतर जागरुक किया जा रहा है तथा किस प्रकार ऑनलाइन बिजली के बिल, टेलिफोन एवं अन्य बिलों का भुगतान अपने मोबाइल से ही घर बैठे कर सकते हैं, इसकी जानकारी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दी जा रही है। मिशन रीव से गांव में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जा रहा है।

साधारण टेस्ट सुविधाओं को अब ग्रामीण घरद्वार पर ही ले पा रहे हैं। इसमें ब्लड टेस्ट, शुगर टैस्ट, टाईफाईड और हेपेटाइटिस बी आदि टैस्ट शामिल है। जैविक खाद तैयार करने के लिए जो घोल उपयोग में लाया जाता है, उसका प्रशिक्षण 7 युवाओं को दिया जा चुका है। चंबा में मिशन रीव सभी ग्रामीण क्षेत्रों में धीरे-धीरे समस्त सेवाओं के साथ पंहुच रहा है।

मिशन रीव के तहत जैविक खाद निर्माण की व्यवहारिक जानकारी के साथ किसानों को प्रशिक्षण

कुल्लु ज़िला में मिशन रीव बना चुका है घर-घर पहचान

कुल्लु, टीम रीव

कुल्लु ज़िला में भी मिशन रीव अब विभिन्न सेवाओं की लॉचिंग कर लोगों को सुविधाओं से जोड़ रहा है। कुल्लु के आनी खण्ड में मिशन रीव द्वारा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न प्रकार के टैस्ट करवाकर कम समय में ही लोगों के टैस्ट रिपोर्ट दिए जा चुके हैं। एक माह में स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से रीव के सदस्यों एवं उनके परिवारों को लाभ दिया गया। इसमें रक्त जांच, स्वास्थ्य जांच नि:शुल्क प्रदान की गई। लोगों ने घर-द्वार पर ही स्वास्थ्य जांच की सुविधा को नायाब बताया तथा मिशन रीव की इसके लिए प्रशंसा की। मिशन रीव द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं में :

- मोबाईल बाईक हैल्थ लैब
- स्वास्थ्य स्लेट के द्वारा लोगों को स्वास्थ्य संबन्धी जानकारियां एवं सुविधाओं को प्रदान किया गया।
- मिशन रीव के अंतर्गत किसानों को जैविक खाद निर्माण का प्रशिक्षण एवं जानकारी प्रदान की गई।

स्वास्थ्य जांच में रक्त नमूनों की जांच सदस्यों को निशुल्क तथा गैर सदस्यों से कम कीमत पर ही सेवाऐं दी गई। ज़िला

समन्वयक मनीश भारद्वाज के साथ पंचायत फैसिलिटेटर एवं अन्य टीम सदस्यों ने बैठकों एवं जांच शिविरों का आयोजन किया गया। शीघ्र ही अन्य सेवाओं के साथ मिशन रीव कुल्लु ज़िला में घर-घर तक पंहुचेगा।

अब न सिलेंडर बुक कराने की टेंशन न बिल जमा कराने की

रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना हुआ आसान

कुल्लू, टीम रीव

पहले बिल जमा कराने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। बाकि के काम रह जाते थे। सिलेंडर बुक कराने और लाने की भी परेशानी रहती थी। लेकिन जब से मिशन रीव क सदस्य बने तब से मिशन रीव के प्रतिनिधि ही हमारे सारे काम कर देते हैं। कुछ ऐसा ही कहना है कुल्लू के महेश का। महेश के मुताबिक पहले छोटे छोटे घरेलु काम जैसे बिजली का बिल जमा करना, बीज खरीदना, गैस सिलेंडर बुक कराना, ये काम खुद की करने पड़ते थे लेकिन अब मिशन रीव ही यह सारे काम कर देता है। रीव प्रतिनिधि जरूरतों के अनुसार सभी काम समय पर पूरा करके देते हैं। इससे परेशानी कम हो गई है और समय की बचत भी हो गई है।

महेश की तरह ही जिला कुल्लू में तीन सौ से अधिक लोग मिज़न रीप के तहत सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। मिशन रीव के तहत स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी और पशुपालन से संबंधित विभिन्न तरह के उत्पाद भी लोगों को घरों तक पहुंचाए जा रहे है। इनके लिए पहले लोगों को शहरों की दौड़ लगानी पड़ती थी।

विकास की बातः कृषि को देगा मिशन रीव नए पंख, निःशुल्क प्रशिक्षण से खुले रोजगार के द्वार

मंडी, टीम रीव

एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान शिमला द्वारा प्रदेश भर में संचालित मिशन रीव की ओर से मंडी जिला के बल्ह, गोपालपुर और धर्मपुर में किसानों को जैविक खाद बनाने की विधि से अवगत करवाया गया। इस अवसर पर शिमला से आए विशेषज्ञ द्वारा किसानों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान भी बताया गया। इस दौरान किसानों में जैविक खेती को लेकर खासा उत्साह देखा गया।

जैविक खाद बनाने व उपयोग की विधियों पर किसानों जानकारी देते हुए रीव टीम

इस मौके पर मुख्य रूप से सहायक जिला समन्वयक अनुज ठाकुर, बल्ह खंड समन्वयक रजनीश शर्मा, गोपालपुर के खंड समन्वयक नवदीप वर्मा, सहायक ब्लाक समन्वयक सतीश कुमार, सहायक ब्लाक समन्वयक अजय कुमार मौजूद रहे। मिशन रीव के बल्ह खंड समन्वयक रजनीश शर्मा ने बताया कि यह विधि बहुत ही सरल और जल्दी परिणाम देने वाली है। यह किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके द्वारा किसान मात्र 30-40 दिनों में जैविक खाद का उत्पादन कर सकते हैं।

किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा मिशन रीव

उन्होंने कहा कि नि:शुल्क खाद बनाने का प्रशिक्षण देने के साथ-साथ किसानों को खाद बेचने के लिए बाजार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है।

पंचायत फेसिलिटेटर को विशेष प्रशिक्षण

मिशन रीव के पंचायत फेसिलिटेटर विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए

मंडी, टीम रीव

ग्रामिणों को सेवाएं देने के लिए आईआईआरडी की ओर से पंचायतों में सेवाएं देने के लिए पंचायत फेसिलिटेटर पीएफ की नियुक्ति की गई है। ये पीएफ मिशन रीव के तहत गांव के लोगों की जरूरतों को पहचान कर उन जरूरतों के मुताबिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए संस्थान की ओर से समय समय पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत हमीरपुर में हाल ही में इन प्रतिनिधियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें शिमला कार्यालय से विशेषज्ञों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। इस दौरान पीएफ को विभिन्न कृषि योजनाओं और ऑनलाइन सर्विसेज प्रदान करने की तकनीकि जानकारी प्रदान की गई ताकि लोगों को ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान की जा सके और साथ ही कृषि योजनाओं की जानकारी भी वह ग्रामिणों तक पहुंचा सके। इस बीच ग्रामिणों को पैन कार्ड बनाने और अन्य कागजी दस्तावेजों को तैयार करने में भी ये पीएफ महत्पूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा जैविक खाद करने का प्रशिक्षण भी ग्रामिणों को निशुल्क प्रदान किया जा रहा है।

प्राथमिक जांच में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं .....

स्वास्थ्य के प्रति हिमाचल के ग्रामीण लोगों का सुस्त रवैया कई बीमारियों को न्यौता दे रहा है। गांव-गांव में लोग अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच नहीं करवाते हैं तथा छोटी-छोटी शारीरिक विकारों को साधारण समझ कर भारी नुकसान कर लेते हैं । ऐसे ही चौंकाने वाले कुछ स्वास्थ्य संबन्धी आंकड़े उस समय सामने आए जब स्वास्थ्य स्लेट के स्वास्थ्य सेवक गांव-गांव जाकर लोगों से मिले और उनकी स्वास्थ्य प्रारंभिक जांच की।

रक्तचाप यानि ब्लड प्रेशर के हिमाचल भर में कुल 3068 प्रारंभिक जांच किए गए जिनमें उच्च रक्तचाप यानि हाई ब्लड प्रेशर 1739 लोगों में पाया गया जबकि 1552 लोग लो बीपी से ग्रसित पाए गए। 313 लोग प्रारंभिक जांच में सामान्य स्थिति में थे। यानि उच्च रक्तचाप के 56.68% लोग, लो बीपी के 50.58% तथा सामान्य श्रेणी में 10.20% लोग हैं । 536 लोग यानि 17. 04% लोग दोनों ही श्रेणियों में हैं जिन्हें लो बीपी और उच्च रक्तचाप दोनों ही है । बीपी की सामान्य रेंज 80-120 रहती है । प्रारंभिक जांच में रक्तचाप के बाद सबसे अधिक समस्या जो सामने आई है वो शुगर को लेकर है । शुगर में कुल 2541 टेस्ट किए गए जिसमें हाई बीपी के 1103 लोग जांच में सामने आए तथा लो बीपी के 65 लोग ग्रसित पाए गए । सामान्य श्रेणी में 1373 लोग थे । नॉन फास्टिंग में हाई बीपी के 1020 और लो बीपी के 25 केस सामने आए । जबकि फास्टिंग में हाई बीपी उपर 83 और लो बीपी के 80 केस सामने आए हैं । मिशन रीव के तहत समस्त हिमाचल प्रदेश में विगत दो माह में कुल 11,458 लोगों की जांच स्वास्थ्य स्लेट किट से की गई है । इसमें महिलाओं की प्रारंभिक जांच पुरुषों के माध्यम से कहीं अधिक हुई है। यानि महिलाऐं इसमें स्वयं की प्रारंभिक जांच के लिए बड़ी तादात में सामने आई है। 2763 पुरुषों के मुकाबले 8674 महिलाओं ने अपनी जांच स्वास्थ्य स्लेट में माध्यम से करवाई । आयु वर्ग में 10-20 आयु के लोगों में 115 तो वहीं 90 की आयु वर्ग में 159 लोगों ने इस सेवा का लाभ लिया। अस्पतालों और टेस्ट लैब की लंबी कतारों से घर में बैठे-बैठे सुलभ व सरल जांच के इस माध्यम स्वास्थ्य स्लेट को लोगों ने निकट भविष्य के लिए अपनाने का उत्साह दिखाया है ।

इसे विडंबना ही कहा जाऐगा कि गांव में स्वास्थ्य के प्रति बहुत बड़े दावे किए जाते रहे हैं जबकि स्थितियां इसके विपरीत है । लोगों को अपने स्वास्थ्य में हो रहे परिवर्तन और अस्वस्थता का पता ही नहीं है क्योंकि नियमित चैकअप ही नहीं किया जाता है । स्वास्थ्य स्लेट के स्वास्थ्य सेवक जब मिशन रीव के तहत गांव-गांव में चैकअप के लिए पहुंचे तो लोगों से बात कर उनकी प्राथमिक जांच की गई जिसमें अधिकतर संख्या किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित पाई गई । ग्रामीण लोगों में महिलाओं ने अधिक संख्या में अपना चेकअप करवाया तथा उसके बाद जांच में पता चला कि कई दिनों से सिरदर्द और बेचैनी का कारण बीपी का बढ़ जाना था । इस पर हैरान करने वाला तथ्य यह है कि लोगों को यह मालूम ही नहीं है कि उनका बीपी बढ़ गया है या उन्हें कोई अन्य रोग होने की आशंका बढ़ रही है । ग्रामीण लोगों को जानकारियों का भी अभाव है जिससे स्वास्थ्य में लगातार बदलाव हो रहे हैं । अधिकतर लोगों ने चिंता, तनाव बदलते खानपान और बदलती जीवन शैली को इसके लिए जिम्मेवार माना । यही राय हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर की भी है । आवश्यक जानकारियां नहीं पता है तो इससे भविष्य के लिए स्वास्थ्य के ख़तरे बढ़ जाऐंगें ।

ग्रामीण क्षेत्र में रोजमर्रा की भागमभाग में लोग अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें अस्पताल तक जाने से लेकर जांच की जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना होता है , साथ ही अस्वस्थ होने के परिणामों की चिंता भी जांच न करवाने का एक कारण है । ऐसे में स्वास्थ्य स्लेट इसे सुगमता के साथ लोगों के स्वास्थ्य जांच के लिए गांव-गांव में एक उचित माध्यम बनता जा रहा है । स्वास्थ्य स्लेट में एक टेबलेट के माध्यम से टैस्ट होते हैं तथा उसकी रिपोर्ट भी जांच के साथ-साथ ही सामने आ जाती है । इसके लिए प्रदेश भर में मिशन रीव के माधयम से स्वास्थ्य सेवक गांव-गांव में जाकर रक्त जांच करते हैं तथा एक टैबलेट के माध्यम से जांच की रिपोर्ट भी सामने ही आ जाती है ।

इसके लिए बहुत बड़ी कोई योग्यता की भी आवश्यकता नहीं है । इसे संचालित करना बेहद आसान है । स्वास्थ्य स्लेट अति आवश्यक तीन बातों पर जांच कर सामने लाता है :

1. क्या आपका स्वास्थ्य सुरक्षित क्षेत्र अथवा दायरे में हैं
2. क्या आपका स्वास्थ्य असुरक्षित ज़ोन में जा रहा है
3. क्या आपका स्वास्थ्य असुरक्षित ज़ोन में जा चुका है

टेबलेट की जांच में प्रारंभिक उपचार एवं जानकारियों के साथ ही लोग स्वास्थ्य के प्रति आश्वस्त हो रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य स्लेट के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश में जांच शिविरों एवं अन्य माध्यमों से आंकड़े सामने आए हैं । जम्मु व कश्मीर तथा उत्तरांचल में तो स्वास्थ्य स्लेट जांच वहां की आंगनबाडियों की कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जा रहा है । हिमाचल में इसे मिशन रीव के माध्यम से रीव के स्वास्थ्य सेवक पूर्ण कर रहे हैं । इस जांच में प्राथमिक तौर पर 7 प्रकार की जांच की गई है तथा भविष्य में इसे 32 प्रकार के टैस्ट संभव बनाए जाऐंगे ।

इन तमाम जानकारियों का पता तब चला जब स्वास्थ्य स्लेट के स्वास्थ्य सेवक गांव में चेकअप/प्रारंभिक जांच के लिए पहुंचे । प्राथमिक प्रारंभिक जांच में अस्वस्थता का पता चलने पर उन्हें रीव क्लिनिक मोबाईल लैब में जांच हेतु परामर्श दिया गया तथा लैब की रिपोर्ट के बाद रीव के विशेषज्ञ डॉक्टर के पैनल में आगामी उपचार हेतु भेजा जाता है ।

मिशन रीव पर सरकार को भी भरोसा

स्कूलों में ड्राप आउट सर्वे की मिली जिम्मेदारी

किन्नौर, टीम रीव

आईआईआरडी की ओर से शुरू किया गया मिशन रीव ग्रामीणों के साथ साथ सरकार का भरोसा जीतने में कामयाब रहा है। मिशन रीव के तहत पंचायत स्तर तक प्रतिनिधियों की तैनाती और विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों को देखते हुए सरकारी संस्थाएं भी मिशन रीव का सहयोग ले रही है। डायट की ओर से जिला किन्नौर में स्कूलों से ड्राप आउट सर्वे का जिम्मा मिशन रीव को सौंपा गया। इसके तहत बेहद बारीकी से मिशन रीव के प्रतिनिधियों ने जिला के सभी स्कूलों और गांवों में जाकर डेटा एकत्र किया है। लोगों का कहना है कि इससे पहले भी कई बार सूचना मिलती थी कि सरकार सर्वे कराती है लेकिन अभी तक गिने चुने घरों में ही सर्वे किया जाता था और जिन गांवों का रास्ता थोड़ा कठिन हैं वहां तक सर्वेयर कभी पहुंचे ही नहीं। लेकिन इस बार मिशन रीव के तहत प्रतिनिधियों की ओर से हर घर में जाकर सर्वे किया गया। रिकांगपिओ के बालकृष्ण नेगी ने बताया कि उनके घर में पहली बार सर्वे करने कोई संस्था पहुंची। उन्होंने कहा कि सर्वे सही तरीके से होने चाहिए ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और सही से नीतियों का निर्माण भी हो सके।

पूह के दुर्गम क्षेत्रों में भी सेवाएं देगा मिशन रीव

इसी माह से लोगों को मिलेगा लाभ

किन्नौर, टीम रीम

किन्नौर में पूह के दुर्गम क्षेत्रों में भी जल्द ही मिशन रीव के तहत लोगों को सेवाएं मुहैया करवाई जाएगी। मिशन रीव के जिला समन्वयक विशाल नेगी के मुताबिक पहले चरण में रिकांगपिओ में लोगों को विभिन्न तरह की सेवाएं मुहैया करवाई गई है। पूह में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां बर्फबारी और अन्य विपरीत परिस्थितियों के चलते लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में मिशन रीव के तहत पूह

में लोंगों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा और साथ ही साथ अपने स्तर पर भी स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी व अन्य ऑनलाइन सेवाएं मुहैया करवाएगा। इसके लिए सभी तैयारियों पूरी कर ली गई है और इस माह के आखिर तक पूह में लोग मिशन रीव के तहत विभिन्न तरह की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

$15-30 trillion loss if girls don't go to school: World Bank

Not educating girls or creating barriers in their school education globally costs between $15 trillion to $30 trillion, the World Bank said in a new report 'Missed Opportunities: The High Cost of Not Educating Girls'as the UN marks "Malala Day".

Women who have completed secondary education are more likely to work and earn on average nearly twice as much as those with no schooling, said WB's "Missed Opportunities: The High Cost of Not Educating Girls" report. The report said that around 132mn girls around the world between the ages of 6 and 17 are still not in school, 75% of whom are adolescents. WB analysis also stated positive outcomes in educating women include a reduction in child marriage, lower fertility rates, etc.

The report goes to say that less than two thirds of girls in low-income countries complete primary school and only one in three girls completes lower secondary school. On an average, women who have a secondary education are more likely to work and they earn almost twice as much as those with no education, it said.

According to the report, today some 132 million girls around the world between the ages of 6 and 17 are still not in school -- 75 per cent of whom are adolescents. "We cannot keep letting gender inequality get in the way of global progress," said World Bank CEO Kristalina Georgieva.

In the 18 countries for which simulations were carried with demographic projection tools, the average reduction in population growth was estimated at -0.18 percentage points, it said, adding that the reductions in annual population growth rates are, however, different depending on which country is considered. "In India, the largest of the 18 countries, the reduction was estimated at only -0.08 percentage point because the country has already gone through much of its demographic transition," the report said.

"For perspective, India's annual population growth rate is currently at 1.2 per cent per year, versus more than two per cent and in some cases three per cent or more per year for many other countries included in the simulations," it said.

कविता

मिशन रीव
गूंगे किसानों को
कुदरत का जीभ है
ये मिशन रीव है
ये मिशन रीव है ।।
लोग यहां स्वस्थ हैं
शिक्षा की नीव है
नित नूतन वादों से
जीवन का दीप है
ये मिशन रीव है
ये मिशन रीव है ।।
आवश्यकता आपकी आकलन हमारा है
मैं नहीं तुम नहीं संकल्प हमारा है
मानव के बीच का निर्मन संगीत है
ये मिशन रीव है
ये मिशन रीव है
जीवन उल्लास है
एक प्यारा गीत है
नृत्य है, उत्सव है
नैसर्गिक सीप है
मोतिया बिखेरता.....
ये मिशन रीव है
ये मिशन रीव है
गांव-गांव, डगर-डगर
सबका ये गीत है
उंचे पहाड़ों से नीचे तराई में
सेवा संकल्प है नैसर्गि प्रीत है
ये मिशन रीव है
ये मिशन रीव है

डा.आर के सिह

चेतना : एक सुखद अहसास की अभिव्यक्ति

मनुष्य जीवन की सार्थकता हमारी अन्त: व बाह्य चेतना की कसौटी पर परिभाषित होती है। बाह्य चेतना मन तथा बुद्धि पर आधारित होते चिरस्थायी नहीं होती तथा मन व बुद्धि के स्तर के उतार-चढ़ाव के अधीन होने के अनुरूप अस्थायी चेतना कही जा सकती है। लेकिन जीवन के अधिकांश भाग को यही चेतना प्रभावित किए रहती है। अन्त: चेतना वास्तिविक चेतना है जो आत्मिक है तथा अन्त:करण की शुद्धता के स्तर से आंकी जा सकती है। अन्त:करण की चेतना आगे चलकर आत्मिक चेतना में परिवर्तित होकर वास्तविक चेतना बन जाती है जिस का मन, बुद्धि व शरीर से कोई सरोकार नहीं होता ।

प्राकृतिक तथा नैसर्गिक प्रक्रिया के अनुसार बाह्य चेतना के पुष्ट होते ही आन्तरिक चेतना की अनुभूति होने लगती है, या यूँ कहे कि चेतना की तीन क्रमिक अवस्थाएँ है- पहले बाह्य चेतना कुछ उन्नति के बाद अन्त:चेतना तथा आगे चलकर आत्मिक चेतना या पूर्ण चेतना । पूर्ण चेतना की स्थिति को प्राप्त करना ही मनुष्य का मूल धर्म है, कर्तव्य है तथा उन्नति की पराकाष्ठा है।

इस मूल गन्तव्य तक पहुँचने के लिए पहला कदम बाह्य चेतना का पुष्ट होना है तथा बाह्य चेतना को हमारा भय, दैनिक परेशानियां व द्वन्द्वात्मक मनोस्थिति प्रभावित करती है। जीवन की जटिलताएं जितनी आसानी से सुलझती जाएं, उतनी ही सकारात्मक हमारी मनोस्थिति होगी, यह एक तथ्य है। आज जब हम 21वी शताब्दि में प्रविष्ट है, जीवन को आसान बनाने के लिए विभिन्न उपाय उपलब्ध हो रहे हैं तथा यही उपाय समाज के एक बड़े वर्ग के लिए कठिनाई भी हैं जहाँ उन्हें किसी न किसी प्रकार के सहयोग की जरूरत रहती है और सेवा सहयोग उपलब्ध न होने से वही मानसिक कुंठा के शिकार होते हैं। एक कुंठित मन स्वयं के लिए, परिवार के लिए तथा समाज के लिए समस्या जनक ही होता है जबकि समाज को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो न सिर्फ अपनी व अपने परिवार की सामान्य समस्याओं का समाधान करें बल्कि इर्द-गिर्द के जनमानस दु:ख दर्द को भी दूर करने में सहायता कर सकें।

जीवन की प्रगति को व्यक्ति या परिवार विशेष की जो भी प्राथमिकताएं हैं उन्हें मूर्त रूप देने में यथासंभव सहयोग मिलने से प्रगति में तीव्रता आएगी। ऐसी ही अवधारणा के साथ मिशन रीव (रूरंलाईजिंग इण्डिया-इम्पावरिंग विलेज़िस) का जन्म हुआ जिसका मूल उद्देश्य यह है कि हम व्यक्ति को , परिवार का अहसास दिला सके कि उन्हें जीवन में निरूसाहित होने की आवश्यकता नहीं हैं, जब भी, जिस भी प्रकार की सहायता या सेवा की जरूरत हो, मिशन रीव के माध्यम से वह सेवा या सहायता उपलब्ध करवाई जा सके वह भी बाजार की अपेक्षा बहुत कम लागत में जिस दिन हमारा ग्रामीण समाज मिशन रीव को हर प्रकार के सम्भव समाधानों का पर्याय मानने लगेगा, उस दिन मिशन की स्थापना का उद्देश्य पूरा होगा। बस समयबद्ध तरीके से लोगों तक यह बात पहुँचाने की आवश्यकता है कि वे मिशन से जुड़ें अपनी समस्याओं को सांझा करें तथा कम लागत पर निश्चित समयाबधि में समाधान पाएँ। ग्रामिणों में सदैव एक सहारा बनेगा कि जब उनकी कोई नहीं सुनेगा, जब उनकी आशा के सभी रास्ते बन्द दिखेंगे, उस घड़ी में मिशन रीव उनका सहयोगी बन खड़ा रहेगा, उस घड़ी की हमें प्रतीक्षा रहेगी।

यही लोगों के जीवन को सुलभ बनाएगा तथा यही मनोस्थिति को सकारात्मक बनाएगा। इसी से चेतना के दरवाजे खुलने शुरू होगें ।

डॉ. एल.सी. शर्मा
प्रधान संपादक

★★★

ग्रामीण विकास के लिए महायज्ञ है मिशन रीव

अगर आपके काम, दूसरे लोगों को जीवन में बड़े सपने देखने और ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं तो निश्चित तौर पर आपमें एक नायक के गुण है।

कहने को यह चंद लाइने हैं लेकिन इन चंद लाइनों में ही मेरे जीवन का सार छुपा है। आत्मिक संतुष्टि, कुछ अलग करने की ललक और समाज के लिए सही मायनों में कुछ करने की चाहत लिए मैं मिशन रीव से जुड़ा। एक मित्र ने जब पूछा कि रीव के द्वारा गांवों का वर्तमान स्वरूप बनाए रखते हुए सशक्तिकरण कैसे संभव है? आप लोग अगर गावों के शहरीकरण की बात करते तो कुछ समझ आता है, मगर क्या आप इसे और अधिक पिछड़ा बनाने की बात नहीं कर रहे?

मित्र की बात में तर्क तो था, मैं सोचता रहा और फिर अध्ययन किया। इस सोच के प्रतिपादक एवं प्रवर्तक प्रबंध निदेश डॉ एल,सी. शर्मा से चर्चा की। चर्चा से एक सवाल निकला, आखिर हम सशक्तिकरण का पैमाना मानते किसे हैं? क्या केवल अंधाधुंध शहरीकरण के द्वारा ही विकास एवं सशक्तिकरण संभव है, या गांव के माहौल, वातावरण, परिवेश और सांस्कृतिक से बिना छेड-छाड़ किये इन्हें स्वावलम्बी और सुविधा संपन्न बनाना सशक्तिकरण कहलाता है?

जब इस प्रश्न का उत्तर सोचता हूँ तो आत्म संतुष्टि और गर्व के मिश्रित भाव मन मे पैदा होते हैं। मिशन रीव एक ऐसी ही सोच है, जिसका जन्म ग्रामीण परिवेश, इसकी आत्मा, संस्कृति और वातावरण को हानि पहुंचाए बिना इन्हें "सुविधा संपन्न स्वावलंबन" की ओर ले जाने के लिए हुआ है।

कृषि एवं पशुपालन सदियों से हमारे ग्रामीण समाज के स्वावलंबन की रीढ़ रहे हैं, मिशन रीव इन दोनों क्षेत्रों में रीव आर्गेनिक्स के माध्यम से केमिकल रहित सुविधाएं तथा सेवाएं ग्रामीणों के घर द्वार पर न्यूनतम संभव समय सीमा में तेज़ी से और संभवत: न्यूनतम कीमत पर उपलब्ध करवा कर कृषि एवं पशुपालन को सशक्त तथा प्राफिटेबल बना कर ग्रामीणों का सशक्तिकरण करेगी।

इसी तरह स्वास्थ्य सुविधाएं जो आज़ादी के 70 साल बाद भी ग्रामीणों के लिए एक स्वप्न ही हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी मिशन रीव अपने हेल्थ डिवीज़न के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के 300 स्टोर खोलने, स्वास्थ्य स्लेट एवं मोबाइल पैथ लैब द्वारा ग्रामीण जनता के घर द्वार पर स्वास्थ्य जांच करने की दिशा में अग्रसर हो चुका है। अन्य दैनिक काम काजी तथा निजी समस्याओं एवं ज़रूरतों का समाधान तथा निराकरण भी अलग अलग पटलों पर किया जाना आरंभ हो चुका है।

ग्रामीण सशक्तीकरण के इस महायज्ञ में अपनी मेहनत रूपी आहुति दे रहे है हर पंचायत में उपस्थित हमारे पंचायत फैसिलिटेटर, ब्लाक स्तर पर ब्लाक कोऑर्डिनेटर तथा जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जिन्हें शिमला से एक सेंट्रल सपोर्ट टीम के तहत आर्गेनाइज किया जाता है। इसी ग्रामीण सशक्तिकरण की कड़ी का एक अन्य आयाम है 'रीव टाइम्स'।

मिशन रीव ने अपने प्रकाशन 'रीव टाइम्स' के माध्यम से ग्रामीणों को मीडिया क्षेत्र में भी प्रतिनिधित्व प्रदान करने का जो बीड़ा उठाया है वो अति सराहनीय है। इस क्रांतिकारी कदम के लिए रीव टाइम्स के संपादक एवं सम्पूर्ण टीम को मेरी शुभ कामनाएं। मेरा विश्वास है कि, (रीव टाइम्स) मिशन रीव नामक ग्रामीण सशक्तिकरण के इंजन को एक उत्प्रेरक (कैटालिस्ट) की तरह गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

सुरेंद्र कुमार
स्टेट कोआरडीनेटर

मिशन रीव एक महकता गुलदस्ता

"बुलंदियों को छूना है इस मिशन का मक़सद,
खुशियां बांटना है इस मिशन का मक़सद,
खुदा भी आसमां से जब जमी पर खुशियां देखेंगा,
वह भी इस रचना से प्रफुल्लित हो जाएगा"

30 सितंबर, 2017 को जब मिशन रीव आरम्भ हुआ तब मात्र कुछ ही लोग थे जिन्होंने इसके उतार-चढ़ाव देखे । आज मिशन रीव समस्त हिमाचल में फैला है । ऐसा लगता है जैसे मिशन रीव ने एक गुलदस्ते का रूप ले लिया हो । यह हमारी रोज़-मर्रा की ज़िन्दगी बन चुका है । मिशन रीव के आने से गांव का हर इन्सान खिल उठा है क्योंकि जहां पहले लोगों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शहर की तरफ जाना पड़ता था, अब वे ज़रूरतें व सुविधाऐं उसे उसके घर-द्वार पर मिलने लगी है जिससे कि वह आत्म-निर्भर व आत्म-सम्मानित हो गया है । मिशन रीव तो हमारे लोगों के लिए वरदान बनकर आया है । मैंने इसे क्रान्तिकारी मिशन इसलिए कहा क्योंकि यह हमारे पूरे परिवेश को बदलने वाला है। इस मिशन से जहां एक तरु लोगों को रोजगार मिलेगा वही वह अपनी संस्कृति व मिट्टी से भी जुड़ाव रहेगा । हमारी युवा पीढ़ी जो रोजगार के लिए अपने गांव-घर से पलायन कर रही है, वह रोजगार के लिए बाहर नहीं भटकेगी और एक बार पुन: हमारे समाज में संयुक्त परिवार होगें, युवा वापिस आएगें तथा लोगों के सपने घर-गांव में ही सेवाओं को प्रदान कर पूरे होगें । अन्त में, मैं यही कहना चाहती हूं कि मिशन रीव हमारे पूरे परिवेश को बदलने का एक आईना है , यथार्थ में बदलता हुआ एक सपना है और यह सपना खुली आंखों से देखा गया सपना है जो दिन प्रतिदिन रंग लाना शुरु कर चुका है ।

सुषमा शर्मा
निदेशक, आईआईआरडी, शिमला

मिशन रीव : दौर बदलने की एक सोच

"हमने सोच को बदला है सितारे खुद ब खुद बदल जायेंगे,
नजर को बदला हमने नजारे अपने आप बदल जायेंगे, "

भारत वर्ष विविधता में एकता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं यह देश अपार प्राकृतिक संसाधानों, सक्षम और असीम प्रतिभाशाली जन संसाधानों से परिपूर्ण है। विकासशील देश होने का खामियाजा अन्य देशों के साथ साथ भारतवर्ष को भी भुगतना पड़ रहा है। विकासशील देशों की विभिन्न समस्याओं में से सर्वाधिक गंभीर समस्या 'गावों से पलायन' से हमारा देश विशेष रूप से जूझ रहा है। इस समस्या के कारण गावों में रोजगार के साधानों की कमी के इलावा मूलभत सुविधाओं का आभाव प्रमुख हैं। शहरीकरण की प्रक्रिया बेहद खतरनाक तरीके से गतिशील है। गांव कस्बों और कस्बे शहरों में तेजी से परिवर्तित हो रहे हैं। इस प्रक्रिया में सब से महत्वपूर्ण विषयों पर अतिशीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी आदर्श परियोजना के बिना अनियमित शहरीकरण का बुनियादी ढांचे पर प्रभाव। भूमि के किसी एक भाग पर अत्यधिक जैविक दबाब। शहरों की परियोजनाओं का बुनियादी ढांचे से मेल का आभाव। आईआईआरडी शिमला ने इस समस्या का गंभीरता से संज्ञान लिया है और गहन विचार विमर्श के उपरांत कुछ सुझाव दिए हैं ।

एक संतुलित भौगोलिक इकाई में रहने के लिए उस इकाई की क्षमता के अनुरूप लोगों का निर्धारण करना । सम्मानजनक तरीके से रहने के लिए अनिवार्य रूप से मूलभूत सुविधाओं का निर्धारण करना । हर गावं के लिए न्यूनतम आधारभूत विकास मानदंडों का निर्धारण करना ।

आवास, सड़क, शुद्ध पेयजल, जल एवं मल निकासी, स्वच्छता, मनोरंजन, रोजगार इत्यादि नागरिक सुवधाओं को कम लागत पर और टिकाऊ प्रोद्योगिकी की पहचान करना। हर भूभाग के लिए कम से कम छह साल की चरणबद्ध तरीके द्वारा समग्र योजना से लोगों के जोड़ना। हर गावंवासी को उत्पादक बनाना उसके लिए अजीविका विकल्प और रोज़गार के अवसर गावं में ही पैदा करना ।

आईआईआरडी शिमला की धारणा है कि गावं में विकास की प्रक्रिया केवल दो तरीकों से ही संभव है, एक बेरोजगार शिक्षित नौजवानों को अपने गांव में ही रोज़गार के अवसर प्रदान करना ताकि वे अपने ही समाज की भलाई के साथ साथ स्वावलम्बी बनकर हर गांव वासी को उसके घर द्वार पर सारी सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम हों ।

'दूसरा एकीकृत विकास में प्रबुद्ध लोगों का समूह बनाना जो हर साल उपयुक्त मंच पर योजनाबद्ध तरीके से सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के संज्ञान में लाये । आईआईआरडी शिमला ने बिना किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान की सहायता के इस मिशन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से की है। इसके परिणाम स्वरूप युवाओं को प्रशिक्षित करके राज्य भर में तैनात किया गया है। पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया गया और स्वास्थ्य सेवाएं सदस्यों एवं गैर सदस्यों को प्रदान की जा रही हैं ।

हमारा प्रयास इस मिशन को सम्पूर्ण भारत वर्ष में लागु करना है । हम मानते हैं कि बिना संसाधानों के भी पढ़े लिखे युवाओं को अपने गांव में ही स्वरोजगार मुहैया करवाया जा सकता है। हमारा यह प्रयास शिक्षित युवाओं के पलायन पर प्रतिबंध लगाने सफल रहा है ।

आईआईआरडी शिमला भारतीय समाजिक परिवेश में मिशन रीव एक अनूठा प्रयास है। इसके तहत न केवल शहरों कि ओर पलायन थम जाएगा बल्कि बेरोजगार युवाओं को अपने ही क्षेत्र में समुचित रोजगार का प्रावधान होगा ।

सुरेश कुमार शर्मा
सह-निदेशक, आईआईआरडी, शिमला

मिशन रीव : सपनों की उड़ान का आकृत रुप

मानव जीवन होने का अर्थ मात्र इतना सा नहीं है कि हम अन्य जीव-जंतुओं से भिन्न है तथा सोचने-समझने की सामर्थ्यता एवं विशेष गुण संपन्न है । यदि जीवन है तो इसके लिए एक परिवेश और सामाजिक ताना-बाना भी है । इसी ताने-बाने में हम जीवन बसर करते हैं और दिन-प्रतिदिन या क्षण-प्रतिक्षण इसकी बेहतरी के लिए, इसे सुख-संपन्न करने के लिए तत्पर रहते है । इसे विडंबना ही कहा जा सकता है कि विश्व की महान क्रांतियों के पीछे भी शायद यही भाव था कि समाज में समानता एवं संपन्नता हो, ग़ैर बराबरी का ढांचा समाप्त हो और हमारा समाज प्रत्येक व्यक्ति को वो सभी सुख-सुविधाऐं सहजता और सरलता से उपलब्ध करवा पाए जिसके लिए दिन-रात का संघर्ष इंसान करता आ रहा है । इसी सोच को सैंकड़ों मतों के साथ विभाजित कर अपने-अपने तरीक़े से सामने लाया गया, जिसका समय भी साक्षी है । अब प्रश्न ये है कि क्या जनसंख्या की पराकाष्ठा पर विराजमान हमारा देश आम जन की सुविधाओं और समस्याओं पर किसी भी प्रकार के सकारात्मक समाधान के साथ विकसित एवं सफल तस्वीर के साथ सामने हैं या नहीं? किसी भी विषय का सर्वे उस विषय की परतों को खोलकर उसका सटीक विश्लेषण करता है । ऐसा ही एक सर्वे वर्षों से गांव-गांव, गलियों, कस्बों और लोगों से गहन चर्चा उपरांत आज मिशन रीव के रुप में हिमाचल प्रदेश में सामने आया है । विकास और सहज सुख-सुविधाओं की सरकारी सफलता अधिकतर फाईलों के दस्तावेज़ी कब्रिस्तान में सुशुप्त अवस्था में रही है । यदि विकास हो रहा है तो फिर दिखाई नहीं दे रहा है या नहीं हो रहा है तो सरकारी आंकड़ों का मायाजाल भ्रमित कर रहा है । गांव में एक बुजुर्ग को उम्र भर ये पता ही नहीं लगता कि उसका मामूली सा सिरदर्द या पेट दर्द अथवा हृद्य की लेशमात्र पीड़ा धीरे-धीरे किसी गंभीर बीमारी का रुप ले रही है । उसके पास समय ही नहीं है कि वो गांव से शहर आकर अस्पतालों की लंबी कतार में दिनभर खड़ा रहकर रात को परेशान सा गांव में पहुंचे । एक दिन में टेस्ट भी पूरे नहीं होते जिसके कारण उसे दोबारा अस्पताल जाना पड़ता है । इस उधेड़बुन में टेस्ट करवाने से तौबा कर लेते हैं । सरकार ऑनलाईन सुविधाओं को प्रत्येक कार्य से जोड़कर पारदर्शिता को अपनाने की बात कर रही है । किंतु क्या गांव का एक साधारण व्यक्ति ऑनलाइन सुविधाओं की समझ रखता है या उसे सरकार ने ऐसे फरमानों के बाद सामान्य जानकारी देने का कोई सुलभ प्रबंध किया है ? इसका उत्तर न में ही होगा । तो फिर गांव का आम किसान, मजदूर क्या अपने बच्चों की स्कूल फीस, राशन का बिल, बिजली, पानी के बिलों आदि का भुगतान ऑनलाईन करवा सकता है? आज भी वो ग्रामीण लोकमित्र केन्द्रों में जाता है और विवशता के साथ सारे बिलों के भुगतान से लेकर अन्य जानकारियों के लिए प्रतीक्षारत रहता है । ये लोक मित्र केन्द्र सभी पंचायतों में नहीं है तथा इनकी कमीशन आदि भी बहुत बार आमलोगों की समझ से परे ही रहती है । महिलाओं की दशा किसी से छिपी नहीं है । उनकी स्वास्थ्य संबन्धी समस्याओं के अलावा उनके सशक्तिकरण के लिए योजनाओं में जो शोरगुल ढोल पीट-पीट कर किया जाता है, वो गांव की धूल में धूसरित होकर गुम हो जाता है । एक गर्भवती महिला को किन-किन बातों का ध्यान रखते हुए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये जानकारी अभावग्रस्त है ।

तो क्या आम इंसान को आधुनिकता के रंग में रंगी 21वीं शताब्दी में विकास एवं सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए भटकना पड़ेगा ? समस्याओं के समाधान के लिए कब तक भटकेगा इंसान ? यही चिंता एक लंबे समय से सर्वे के द्वारा सामने आई और फिर जन्म हुआ मिशन रीव का । डॉ. एलसी. शर्मा एक समाजसेवी जिन्होंने इस मिशन को आधार बनाकर हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए घरद्वार पर ही समस्त सुविधाओं को पहुंचाने और आमजन को लाभान्वित कर उनके सपनों को पूरा करने में सारथी की भूमिका में मिशन रीव का जन्म हुआ । आरंभिक दौर हालांकि कठिनताओं की कसौटी पर परखा गया किंतु वर्तमान तो रीव के साथ नए आयाम गढ़ने की तैयारी में दिखाई दे रहा है । चांद-तारों से पहले आमजन को मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है । उसका जीवन सफल बने, स्वस्थ रहे, खुशहाल हो, यह प्राथमिकता समस्त गतिविधियों, याजनाओं एवं कार्यक्रमों की होनी ही चाहिए । रीव ने इन सब बातों को समेट कर आम जन के दरवाजों पर खटखटाहट की और यह दस्तक एक इंसान को सुविधाओं और उनकी परेशानियों से मुक्त करने की ओर अनुठी पहल थी । आज धीरे-धीरे लोग मिशन रीव को अपनाने में सहजता से आगे आकर अपनी दु:ख-तक़लीफें इसे सौंप कर सुखी -संपन्न जीवन की राह पर बढ़ने के लिए आगे आ रहे हैं । गांव-गांव जाकर फेसिलिटेटर बुजुर्गों को स्वास्थ्य स्लेट के माधयम से जब घर की चारपाई पर बैठकर कुछ ही मिनटों में टेस्ट कर उसकी रिपोर्ट उनके बेटे या बहु के मोबाईल पर बीप की आवाज़ से आती है तो उनकी प्रसन्नता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है । गर्भवती महिलाओं की जांच घर पर ही कर आवश्यक सावधानियां बताकर जच्चा-बच्चा की सुरक्षा का जिम्मा भी रीव के सेवाकर्मी बाखूबी कर रहे है। प्रारंभिक उपचार के लिए जब रीव बाईक पर स्वास्थ्य पिटारा लेकर संकरी गलियों से घर पर पहुंचता है तो एक बीमार व्यक्ति को स्वस्थ होने की निश्चिंतता और अधिक बढ़ जाती है । किसान सरकारी विभागों के अनुदान तथा फसलों के बीजों के वितरण के लिए प्रतीक्षारत रहता है । ऐसे में कृषि जानकारी के साथ-साथ बेहतर उपकरण व बीजों की उपलब्धता यदि घरद्वारा पर ही हो तो खेती में सुधार के साथ ही किसानों के जीवन को सुलभ और सफल बनाया जा सकता है । इस उद्देश्य को रीव ने पूरा करने का बीड़ा उठाया है । युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं को तलाशना आज सबसे बड़ा मुद्दा है । किंतु मिशन रीव में इसका भी सरलीकरण हुआ है और रोजगार की अपार संभावनाऐं युवाओं के सामने है । कला-कौशल विकास और हुनर के हिसाब से प्रदेश भर में युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं ।

एक ऐसा रोजगार जिसे युवा पलायन किए बिना घर और अपने गांव में रह कर ही कर सकता है और रोजगार को प्राप्त करने के बाद ग्राम विकास और अपने समाज से सामजस्य बिठा कर आगे बढ़ सकता है । ऐसे ही लक्ष्य के साथ मिशन रीव 50 हज़ार से अधिक के रोजगार के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है । इसके तहत हज़ारों बेरोजगार तो अपना पंजीकरण करवाकर रीव से रोजगार प्राप्त कर चुकें हैं । इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि रीव ने अवसरों को सामने रखा है जिसे युवा यदि लाभ लेना चाहे तो रोजगार के साथ-साथ अपने हुनर में भी निखार ला सकता है । उद्यमिता के क्षेत्र में इसे क्रांन्तिकारी पहल कहा जा सकता है । इतना ही नहीं, जेनरिक औषधि के क्षेत्र में 300 से अधिक स्टोर के खुलने तथा आमजन को घर पर ही सस्ती दवाईयों का वितरण एक अनूठी पहल कही जा सकती है ।

एक इंसान आज की भागदौड़ में इतना व्यस्त है कि उसके पास बच्चों की फीस जमा करने, जमाबंदी या ततीमा कटवाने, बिलों के भुगतान के लिए लंबी कतारों में खड़े रहने का समय नष्ट करें.....यह जिम्मेवारी अब रीव ने स्वयं के कांधों पर उठाने की ओर कदम बढ़ाया है ।

इतिहास साक्षी है कि कोई भी जनभावनाओं और आकांक्षाओं से पूर्ण सोच ठोकरें खाती हुई, परिष्कृत होकर प्रेरणा बन जाती है । ऐसी सोच को मूर्त रुप देने और इंसान को चिंता मुक्त करने का लक्ष्य लेकर ही मिशन रीव जनांदोलन बनता जा रहा है । सबकी सुविधा - सबका विकास के जिस उद्देश्य को रीव लेकर चला है, भविष्य में इसे हालांकि अनेक चुनौतियों से दो-चार होना होगा किंतु इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि लोगों ने जिस तरह से इसे अपनाने के लिए आतुरता दिखाई है उससे इसकी सफलता की ओर बढ़ते कदमों की पदचाप समझा जा सकता है ।

सुविधाओं का लाभ लेकर जो लोग रीव से जुड़े हैं उनका विश्लेषण तो कम से कम यही कहता है कि - **जीवन से पहले और जीवन के उपरांत तक मिशन रीव की सेवाऐं समर्पित भाव से गांव में भागीरथी बन कर आई हैं ।**

हेम राज चौहान
सहायक संपादक,द रीव टाइम्स
mail: chauhan.hemraj09@gmail.com

IT A GAME CHANGER FOR MISSION RIEV

Mission RIEV through its innovative interventions 'Swasthya Slate', 'RIEV Clinic Mobile Path Lab' and 'Generic Medicine Outlets' is trying to bring in a significant change in rural peoples outlook in Himachal Pradesh towards their health and health related issues. Swasthya Slate and RIEV Clinic Mobile Path Lab is a good example where marriage of IT & innovation is playing an important role in providing, maintaining and generating health reports of rural people.

Swasthya Slate ('Primary Health Screening' tool) uses handheld Tablet to informs the person about his health status i.e. whether he/she falls in safe zone or he/she is at the verge of a lifestyle diseases or he/she is in the danger zone and need further intervention. The basic health test helps in speedy intervention. The technology used is so user friendly that it hardly requires any training or profession education.

In yester-years we used to go to a pathology lab to do the testing for that people in rural areas need to travel from the village to nearby town or hospital where the pathology lab is available and all this consumes their time and money. The RIEV Mobile Path Lab which is an IT enabled innovative path lab in a suitcase, helps in identifying health related issue. The report is generated in much lesser time compared to existing path labs and can do 72 tests and the service is provided at the door step. The reports are generated and shared online or through SMS on mobile. Thus saving efforts, time and money of rural dwellers.

Agriculture

With technology intervention Mission RIEV will be imparting the rural people about their land and soil health through soil test. The soil test lab is capable to do various test which tells the type of deficiency of the soil. Mission RIEV's intervention will help in provide customise solutions unique to each land. This would help in increasing the productivity, crop rotation, soil health longevity and the earning of the farmers or the land owner in the villages.

Education

In education, Mission RIEV is working on digitising the school education system. We are enabling the education through digitisation, E-Learning, and M-Learning. The technology interventions will help in taking classes without the teacher being physically available in the classroom. The content, book, and assessment are present in mobile and laptop, which can be accessed without boundary of school and country.

The above are small glimpses of initial IT enabled technological intervention used by Mission RIEV. A small step towards giant leap of IT and IT based interventions within and through Mission RIEV. Lot more to come ...

Ranjan Mohanti
Head IT, IFTI

गावों के विकास से साकार होगा गांधी का सपना

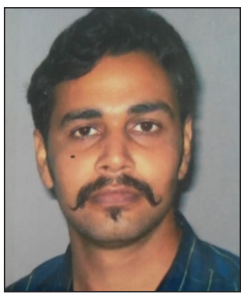

गांधी जी ने कहा था कि भारत का भविष्य इसके गाँव में बसता है। इस कथन को मैं ऐसे समझता हूँ कि गांव को देश की सबसे छोटी इकाई समझा जा सकता है। आज भी हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या गाँव मे ही निवास करती है। यदि हम मुल्यों की बात करें जैसे एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता, प्रकृति से जुड़ाव आदि गावों में आज भी मौजूद हैं।

शहरों की स्थिति अलग है। बढ़ते औद्योगीकरण के चलते इन मुल्यों की उपेक्षा हुई है और संतोष, करूणा एवं सहयोग जैसे मूल्यों की जगह प्रतिस्पर्धा अपने आपको बेहतर प्रदर्शित करना आदि ज्यादा जरूरी हो गए हैं जो एक स्वस्थ समाज के लिए ठीक नहीं है।

गांधी जी का मानना था कि यदि हम एक स्वस्थ और ज्यादा स्थायी समाज चाहते हैं तो हमें गाँव एवं वहाँ के मूल्यों पर विचार करना चाहिए। हमें गांव के विकास पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम उन विचारों को पोषित कर सके जो गांव में पल रहें हैं।

गांव की इसी कल्पना के करीब मूर्त रूप देने के उद्देश्य से मिशन रीव की स्थापना 2017 मे हुई। इसका मुख्य उद्देश्य गांव को मजबूत बनाना है और इस तरह से देश को मजबूती प्रदान करना है।

हम चाहते हैं के अधिक से अधिक संख्या में लोग इससे जुड़े अपनी समस्याऐं हमे बताएं हम क्या सहयोग कर सकते हैं उस दिशा में हम मिलजुल कर काम करें और एक बेहतर गांव का पुनर्निर्माण करें । गांव के युवा जो अपने गांव को जानते हैं, गांव को समझते हैं और सबसे खास बात यह की अपने गांव के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हैं वे हमारे साथ जुड़ें । यह कारवां बढ़े।

गौरव द्विवेदी
सिनियर ऑपरेटिंग ऑफिसर

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में हिमाचल अव्वल

एसीएस बीके अग्रवाल ने दिल्ली में ग्रहण किया अवार्ड

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य, हि.प्र. बीके अग्रवाल को सम्मान प्रदान करते हुए

शिमला, टीम रीव

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के तहत अपने बेहतर प्रदर्शन के दम हिमाचल ने देश भर में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य बीके अग्रवाल को नई दिल्ली में पीएमएसएमए के 'आई प्लैज फोर 9' अचीवर्स पुरस्कार समारोह में इस पुरस्कार से सम्मानित किया।

बी.के. अग्रवाल ने कहा कि केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को पीएमएसएमए क्लीनिकों में सर्वाधिक गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच करवाने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि हिमाचल सरकार ने यह अभियान अगस्त 2016 में आरंभ किया और इसके अंतर्गत 495 पीएमएसएमए क्लीनिक स्थापित किए।

प्रदेश सरकार, अगस्त 2016 से मई, 2018 तक पंजीकृत 1,28,058 गर्भवती महिलाओं में से 87414 (68.26 प्रतिशत) महिलाओं की इन क्लीनिकों में चिकित्सकों द्वारा प्रसव पूर्व जांच करवाने में सफल रही। यह अनुपात सर्वाधिक है तथा दोबारा प्रमाणित करता है कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य मानकों के संबंध में अग्रणी राज्यों में आता है।

उन्होंने बताया कि पीएमएसएमए के तहत गर्भवती महिलाओं की हर महीने की नौ तारीख को चिकित्सकों की ओर से प्रसव पूर्व जांच की जाती है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए निजी क्षेत्र से स्वयं सेवा करने वाले चिकित्सकों पर विशेष बल दिया जा रहा है।

150 करोड़ से महकेगा हिमाचल

शिमला, टीम रीव

हिमाचल प्रदेश में फूलों की खेती को व्यापक बढ़ावा देने के लिए 150 करोड़ रुपये की एक पंचवर्षीय महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है, जिसके तहत प्रगतिशील कृषकों को फूलों की खेती को बड़े पैमाने पर अपनाने के प्रति प्रेरित किया जाएगा। हिमाचल पुष्प क्रान्ति नामक इस नई योजना के तहत इस वर्ष 10 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे, जिसमें कृषकों को अनेक प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है ताकि वे पुष्प खेती को अपनाने के लिए आगे आएं।

पुष्प क्रान्ति योजना को लागू करने के लिए बागवानी विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है । इस समय प्रदेश में लगभग 5 हजार कृषक 643 हैक्टेयर भूमि में फूलों की व्यावसायिक खेती कर रहे हैं जिससे लगभग 87.25 करोड़ रुपये का कारोबार हो रहा है।

प्रदेश में मुख्यत: गेंदा, गुलाब, ग्लैडियोलस, गुलदाउदी, कारनेशन, लिलियम, जरबैरा तथा अन्य मौसमी फूल उगाए जा रहे हैं। प्रदेश में इस समय 'कट फ्लावर' का उत्पादन लगभग 16.74 करोड़ रुपये का हो रहा है। खुले बिकने वाले गेंदा और गुलदाउदी जैसे फूलों का यहां लगभग 12347 मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है। हिमाचल पुष्प क्रान्ति योजना में ग्रीन हाउस तथा अन्य नियंत्रित व्यवस्था जैसे शेड नेट हाउस स्थापित करने के लिए कृषकों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा ताकि वे विदेशी फूलों-जिनकी राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय मण्डियों में विशेष मांग रहती है, की खेती कर सकें। प्रदेश में एलस्ट्रोमेरिया, लिमोनियम, आइरिस, ट्यूलिप तथा आर्किड जैसे फूलों की किस्मों को उगाने की व्यापक सम्भावनाएं हैं। प्रदेश में इस समय छः फूलों की नर्सरियां स्थापित की गई हैं, जो शिमला के नवबहार और छराबड़ा, सोलन जिला के परवाणू, कुल्लू के बजौरा तथा कांगड़ा जिला के धर्मशाला तथा भटुआं में स्थित हैं। इसके अलावा चायल और पालमपुर में माडल फूल उत्पादन केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें गुणवत्ता वाली फूलों की किस्में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। नई योजना में फूल उत्पादकों की सहकारी समितियां बनाने पर भी विशेष बल दिया जाएगा। इस समय प्रदेश में लगभग 8फूल उत्पादक सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं।

हिमाचल में डेंगू की दस्तक, सौ से अधिक लोग चपेट में

शिमला, टीम रीव

हिमाचल के दो जिलों में डेंगू ने पांव पसार लिए हैं। अब तक 115 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जिला बिलासपुर में डेंगू से पीड़ित लोगों का आंकड़ा 90 पहुंच गया है। यहां प्रशासन के भरसक प्रयासों के बावजूद रोजाना दो-तीन नए मामले आ रहे हैं। सोलन के परवाणू में भी 25 मामले आए हैं। बरसात में नालियों और गड्ढ़ो में पानी इक्टठा होने से डेंगू फैल रहा है। बिलासपुर के डियारा सेक्टर में सबसे ज्यादा 62 लोग चपेट में आए हैं। जिले में पहला मामला 28 मई को आया था। सोलन का परवाणू डेंगू के हिसाब से प्रदेश में सबसे संवेदनशील है। यहां हर साल सबसे ज्यादा मामले आते हैं। बरसात में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने दोनों जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। डेंगू मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है।

सामान्य बुखार की तुलना में डेंगू से होने वाला बुखार काफी दर्द देता है। डेंगू होने पर सिरदर्द, जोड़ों में दर्द, तेज ठंड लगकर बुखार के साथ चिड़चिड़ापन होने लगता है। भूख कम लगती है। डेंगू बुखार से रोगी की त्वचा ठंडी पड़ जाती है। उल्टी और दस्त होते हैं। शरीर पर लाल-गुलाबी चकते पड़ जाते हैं। डेंगू के लक्षण 3 से 14 दिन बाद दिखते हैं। डेंगू से बचाव के लिए पानी जमा न होने दें। मच्छरदानी लगाएं और पूरी बाजू के कपड़े पहनें।

राष्ट्रीय खेलों में हिमाचल अव्वल

शिमला, टीम रीव

स्पेशल ऑलम्पिक भारत द्वारा गांधीनगर गुजरात में युवा सेवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 5 से 9 जुलाई तक करवाया गया।

10 स्वर्ण पदकों के साथ हिमाचल ने झटके कुल 33 मेडल

भारत के 25 राज्यों से प्रतियोगियों ने लगभग 1000 विशेष खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश से 26 विशेष खिलाड़ियों व 5 प्रशिक्षकों ने एथलेटिक्स, बैडमिंटन, वॉलीबाल फुटबाल में भाग लिया। हिमाचल प्रदेश ने इन खेल प्रतियोगिताओं में 10 स्वर्ण, 10 रजत व 13 कांस्य पदक प्राप्त किए।

अब एनडीआरएपफ करेगी चूड़धार से लापता मासूम श्रुति की तलाश

2 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी लापता

सिरमौर के चूड़धार चोटी के पास तीसरी नाम की जगह से 2 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई श्रुति की तलाश के लिए अब राज्य सरकार एनडीआरएफ की मदद लेगी। इसके लिए सिरमौर पुलिस ने डीजीपी सीताराम मरडी को चिट्ठी लिखी है।

श्रुति की तलाश के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। हिमाचल पुलिस के लगभग 50 जवान जंगल का कोना-कोना छान रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। पुलिस अधिकारियों का कहना था कि सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्हें भेड़-बकरियों के कंकाल मिले, लेकिन श्रुति का कोई सुराग नहीं मिला।

गौरतलब है कि शिमला के चौपाल की रहने वाली श्रुति का परिवार 1 जुलाई रविवार को चूड़धार मंदिर में माथा टेकने गया था। सोमवार को घर लौटते समय तीसरी नामक स्थान पर श्रुति को टॉफियां लेने के लिए कुछ दूर अकेला भेज दिया था। इसके बाद जब बच्ची लौटकर नहीं आई तो उसकी तलाश की। उसके बाद से उसका कोई अता-पता नहीं है।

वहीं, पुलिस इस मामले में कई पहलुओं पर ध्यान दे रही है। जंगल में जानवरों के हमले के साथ ही आपराधिक नज़रिये से भी इसकी जांच की जा रही है। एएसपी सिरमौर वीरेंद्र ठाकुर ने बताया कि सर्च अभियान जारी है। मोबाइल डंप डाटा का भी सहारा लिया जा रहा है। 50 से अधिक जवान चूड़धार के जंगलों में ग्रामीणों के साथ तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं।

उन्होंने कहा कि बच्ची की तलाश के लिए एनडीआरएफ को बुलाया जा रहा है। इसके लिए सिरमौर पुलिस ने डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। वहीं, पुलिस ने पहले ही बच्ची के लापता होने पर आईपीसी की धारा 363 के तहत मामला दर्ज किया है। समाचार लिखे जाने तक श्रुति का कोई पता नहीं चल पाया था।

'गुड़िया अनसुनी चीख' पुस्तक का विमोचन

गुड़िया के परिजन एवं लेखक पुस्तक का विमोचन करते हुए

शिमला, टीम रीव

कोटखाई गुड़िया रेप एंड मर्डर मामले को एक साल हो गया। गुड़िया मामले पर मदद सेवा ट्रस्ट ने एक किताब गुड़िया एक अनसुनी चीख लिखी है। किताब का विमोचन रिज पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे गुड़िया के पिता के साथ पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी ने किया। यह किताब अश्विनी वर्मा ने लिखी है। किताब में 4 जुलाई 2017 से लेकर अब तक मामले में क्या हुआ इसका जिक्र है। किताब में पुलिस और सीबीआई की जांच के बारे विस्तार से बताते हुए उस पर कई सवाल खड़े किए गए हैं। वहीं, गुड़िया के पिता ने पी एम नरेंद्र से न्याय की गुहार लगाई है।

16 साल की नाबालिग अपने घर से भाई के साथ स्कूल के लिए जाती है। 4 जुलाई 2017 को नाबालिग लापता हो जाती है। 6 जुलाई को कोटखाई के जंगल में बिना कपड़ों के गुड़िया का शव मिलता है। आज इस मामले को एक साल बीत गया है, लेकिन अब तक कोटखाई गैंगरेप-मर्डर केस सुलझ नहीं पाया है। हालांकि सीबीआई ने मामले में एक चरानी को गिरफ्तार किया है। लेकिन, परिजन इससे खुश नहीं हैं। सीबीआई की जांच पर गुड़िया के ही पिता ने सवाल खड़े किए हैं और सीबीआई द्वारा बनाए गए आरोपी नीलू ही नहीं और भी लोगों के शामिल होने की बात कर रहे हैं। सीबीआई जांच पर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने भी सवाल खड़े किए हैं

प्रदेश के उद्योग में 70 नहीं अब 80 फीसदी हिमाचली

मत्रीमण्डल की अध्यक्षता करते माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर

शिमला, टीम रीव

हिमाचल सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 10 जुलाई हो हुई मंत्रिमंडल ने प्रोत्साहन सहायता, छूट और हिमाचल प्रदेश औद्योगिक इकाई सुविधाएं 2011 से संबंधित नियमों में आवश्यक संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत राज्य में उद्योगों को राज्य सरकार से जीएसटी के हिस्से के वापस करने का प्रावधान किया है। उद्योगों को राज्य में 70 की बजाय 80 फीसदी रोजगार स्थानीय लोगों को देना होगा। उद्योगपतियों से राज्य में रिन्यूवल के समय वसूली जा रही फीस को सरकार ने 50 फीसदी से कम कर ही है। पहले औद्योगिक प्लाट पर सरकार रिन्यूवल पर 50 से लेकर 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फीस वसूलती थी, अब इसे कम कर सरकार ने 20 से लेकर 5 रुपए तक प्रति वर्ग मीटर कर दिया है।

एमबीबीएस चिकित्सकों के भरे जाएंगे 200 पद

हिमाचल शिमला, टीम रीव

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माधयम से नियमित आधार पर एमबीबीएस चिकित्सकों के 200 पद भरने तथा हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माधयम से स्टाफ नर्सों के 714 पद अनुबन्ध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

हिमाचल मंत्रिमण्डल ने एपीएल राशनकार्ड धारकों को प्रदान की जा रही चीनी का मूल्य 29 रुपये प्रति किलो से घटाकर 24 रुपये प्रति किलो तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लाभार्थियों को 18 रुपये प्रति किलो से घटाकर 13 रुपये प्रति किलो करने का भी निर्णय लिया।

आम तथा सेब का प्रापण मूल्य 50 पैसे बढ़ा।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी मध्यस्थता योजना के तहत आम तथा सेब फलों के प्रापण के लिए समर्थन मूल्य लागू करने को भी मंजूरी दी। निर्णय के तहत आम तथा सेब का प्रापण मूल्य वर्तमान दरों से 50 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ाया गया।

प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमण्डल ने प्रोत्साहन सहायता, छूट तथा हिमाचल प्रदेश औद्योगिक इकाई सुविधाएं 2011 से सम्बन्धित नियमों में आवश्यक संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की।

चम्बा जिला के पांगी में मैसर्ज अपोलो हास्पिटलज इन्टरप्राइजिज लिमिटेड के माध्यम से टैली-मेडिसन सेवाएं आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की।

शुरू होगी डिजी-पे प्रणाली

मंत्रिमण्डल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पारदर्शिता लाने तथा लोगों की सुविधा के लिए सामान्य सेवाएं केन्द्र योजना-विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों में आधार आधारित नकदी रहित लेन-देन के लिए डिजीपे प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया।

मंत्रीमंडल के फैसले

- एमबीबीएस चिकित्सकों के भरे जाएंगे 200 पद
- शुरू होगी डिजी-पे प्रणाली

मध्यस्थता योजना के तहत आम तथा सेब फलों के प्रापण के लिए समर्थन मूल्य लागू

गगल तथा भुंतर एयरपोर्ट पर एटीआर-72

सरकार ने केंद्रीय नागरिक उड्यन मंत्रलय को भेजा प्रस्ताव

शिमला

हिमाचल की हवाई पट्टियों पर राज्य सरकार बड़े जहाज उतारने की तैयारी में है। गगल तथा भुंतर एयरपोर्ट पर एटीआर-72 उतारने की संभावनाओं के लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय नागरिक उड्यन मंत्रलय को प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश सरकार दोनों हवाई पटियों के विस्तारीकरण और पर्याप्त जमीन देने को तैयार हो गई है। सियासी अड़चनों के चलते प्रदेश की तीनों हवाई पटियों शिमला, धार्मशाला और कुल्लू का विस्तारीकरण लटका है। इस कारण राज्य में बड़े जहाजों की लैंडिंग का सपना अभी तक साकार नहीं हो पाया है। गगल हवाई अड्डे पर एटीआर-72 की लैंडिंग का प्रस्ताव पिछले डेढ़ दशक से कागजों में ही है। विस्थापन तथा जमीन के अन्य मसलों के कारण पिछली तीन सरकारें अपनी इच्छाशद्रि दिखाने में असफल रही हैं। भुंतर हवाई पटी का विस्तारीकरण भी सियासत का शिकार है। बहरहाल, जयराम सरकार ने पर्यटन को पंख लगाने के लिए कई साहसिक फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में बड़ी जहाजों की लैंडिंग का प्रस्ताव भेजा गया है।

बीबीएमबी मामला कोर्ट जाएगी हिमाचल सरकार

भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में हिस्सेदारी के मामले पर हिस्सेदारी को लेकर दशकों से टालमटोल कर रहे पंजाब के साथ हिमाचल ने अब कड़ा रूख अख्तियार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हिमाचल को पंजाब से अपना हक नहीं मिल रहा। हिमाचल को पंजाब से बीबीएमबी की हिस्सेदारी से दो हजार करोड़ रुपये से अधिाक की रकम मिलनी है। सुप्रीम कोर्ट भी हिमाचल के हक में फैसला दे चुका है। उसके बाद भी पंजाब की टालमटोल से नाराज हिमाचल सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करने की तैयारी की है।

हिमाचल व पंजाब के पुनर्गठन के समय कुछ इलाके हिमाचल में शामिल हुए थे। भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के तहत चल रही बिजली परियोजनाओं में हिमाचल का हिस्सा जो पहले ढाई फीसदी था, पुनर्गठन के बाद 7.19 फीसदी तय हुआ था। अपने हक के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और सात साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के पक्ष में फैसला दिया था।

एथलीट सीमा और कब्ड्डी खिलाड़ी डिंपल को खेलो इण्डिया स्कॉलरशिप

बैंकॉक में झंडे गाड़ने वाली एथलीट सीमा और कबड्डी खिलाड़ी डिंपल ने अपने मेहनत के दम पर खेलो इंडिया स्कॉलरशिप हासिल की है। इस स्कॉलरशिप के तहत उन्हें अगले 8 साल तक हर साल 5-5 लाख रुपये मिलेंगे। यानी 8 साल तक इन दोनों खिलाड़ियों को 40-40 लाख रुपये स्कॉलरशिप के अंडर दिए जाएंगे। यह पैसा दोनों खिलाड़ियों की खेल हुनर का तराशने एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं में खर्च किए जाएंगे।

जानकारी के मुताबिक, मार्च माह में हुई पहली खेलो इंड़िया राष्ट्रीय स्कूली प्रतियोगिता के बाद कबड्डी खिलाड़ी डिंपल का नाम स्कॉलरशिप के लिए नामित हो गया था। लेकिन खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों की असल आयु का पता लगाने को लेकर इस योजना के संशोधन करते हुए टीडब्ल्यू-3 टेस्ट निर्धारित किया था। जून माह में हुए टीडब्ल्यू-3 टेस्ट के बाद अब मंत्रालय ने इन दोनों खिलाड़ियों की सूची जारी की है। दोनों खिलाड़ियों को अंडर-17 आयु वर्ग में इस स्कॉलरशिप लगी है। दोनों खिलाड़ियों को चयन फरवरी माह में दिल्ली में हुई पहली खेलो इंड़िया खेलों और पुराने खेल प्रदर्शन के आधार पर हुआ है।

क्या है करियर बैकअप

एथलीट सीमा चंबा की रहने वाली हैं और वे साईं हॉस्टल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। उन्होंने हाल ही में 3000 मीटर दौड़ की धाविका सीमा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक कांस्य और एक रजत पदक हासिल किया। साथ ही उनके पास राष्ट्रीय स्तर के करीब 15 मेडल और 3 राष्ट्रीय रिकार्ड हैं। गरीब परिवार से संबंध रखने वाली सीमा 18 अक्टूबर से अर्जेंटिना में होने वाली यूथ ओलंपिक बेनिक ऐयरस-2018 की तीन हजार मीटर दौड़ में सीमा देश का प्रतिनिधित्व करेगी। वहीं, जिला शिमला के चौपाल से संबंध रखने वाली डिंपल की 2015 एंट्री हुई थी। साई टीम की कवर खिलाड़ी डिंपल के नाम राष्ट्रीय स्तर पर दो गोल्ड और दो सिल्वर मेडल है। खेलो इंड़िया में डिंपल ने रजत पदक जीता है।

क्या होता है टीडब्ल्यू-3 टेस्ट?

टीडब्ल्यू-3 खिलाड़ी से सटीक आयु का पता लगाने के लिए होता है। इस टेस्ट में खिलाड़ी के बाजू की हड्डी का टेस्ट किया जाता है। इससे खिलाड़ी की आयु का सही पता लग जाता है। भारत में सबसे पहले क्रिकेट में सही आयु जानने के लिए टीडब्ल्यू-3 मेडिकल टेस्ट का प्रयोग किया जाता था। अब यह सभी खेलों के लिए अनिवार्य कर दिया है।

उत्तर भारत के मच्छरों पर शोध करेंगे पुडुचेरी के विशेषज्ञ

डेंगू की रोकथाम को बिलासपुर में डेरा जमाए पुडुचेरी की टीम पूरे उत्तर भारत में मच्छरों पर शोध करेगी। वैज्ञानिकों की टीम बिलासपुर के बाद हिमाचल के लाहौल स्पीति, कुल्लू, चंबा और मनाली भी जाएगी।

मच्छरों को पकड़ कर यह टीम शोध के लिए अपने साथ ले जाएगी। टीम के साथ आए वैज्ञानिकों ने अनौपचारिक बातचीत में बताया कि वह पूरे उत्तर भारत से मच्छरों को पकड़ेगी। जिसके बाद अपने साथ पुडुचेरी ले जाएगी।

यहां पर इन मच्छरों पर शोध किया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से उन्हें इस कार्य का जिम्मा सौंपा गया है। इस शोध के तहत टीम सदस्य उन तमाम स्थानों का दौरा करेंगे जहां मच्छर होते हैं और इनका लोगों पर असर पड़ रहा है।

वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर भारत में इस समय मच्छरों का प्रकोप चल रहा है। इसी को देखते हुए पुडुचेरी से आग्र टीम मच्छरों को पकड़ रही है। जिन्हें वह अपने साथ ले जाएगी। उन्होंने बताया कि मच्छरों पर शोध से मच्छरों की प्रजातियों की सूचीब) किया जाएगा।

यह मच्छर किस तरह के वायरस के वाहक बन रहे हैं और इसका मानव जीवन पर कैसा और कितना असर पड़ रहा है, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। इस शोध के आधार पर मच्छरों का जीवन चक्र और सबसे ज्यादा पनपने की स्थितियों को चिन्हित किया जाएगा। अब तक जहां से भी मच्छर पकड़े गए हैं, वहां की लोकेशन से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट बनाग्र गग्र है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में सब कुछ सही नहीं

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सड़कें हमारे देश और आमजन की जीवन रेखा है। ग्रामीण विकास की धूरी है सड़कें। इसी मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) से गांव-गांव को जोड़ने के लिए इसे एक सशक्त कदम कहा जा सकता है। भारत के गांवों को जोड़ने के लिए केन्द्रीय सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)के क्रियान्वयन में भारी विसंगतियां सामने आई है। फंड के विभाजन, तकनीकि स्वीकृति के साथ ही टेंडर जारी करने, अपूर्ण परियोजना एवं कुछ गांवो को प्राथमिकता के साथ महत्व देना आदि में विसंगतियां पाई गयी है। वर्ष 2018-2019 के लिए केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000/- करोड़ रुपये जारी किए हैं। कार्यक्रम की छानबीन करने वाले संसदीय पैनल ने पाया है कि 11 राज्यों में 608 कार्यों के टेंडर उन कार्यों की तकनीकि स्वीकृति के पूर्व ही मांग लिए गए थे और अन्य 7 राज्यों में 73 सड़क कार्य बिना किसी सही औपचारिकताओं के पूर्ण दिखाए गए हैं जबकि बहुत से गांव जो सड़क की प्रतीक्षा में थे, 9 राज्यों के कुछ

चहेते गांवो को अन्य गांवो के ऐवज़ में बहुउद्देशिय सड़क नेटवर्क से जोड़ा गया है।

योजना को ज़मीनी स्तर पर लागू करने और उसकी वास्तविकता को जब देखा गया तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 28 राज्यों के 173 ज़िलों के 582 सड़कों के निर्माण पर 1,223 करोड़ खर्च किए गए हैं जिनमें से यह पाया गया कि 166 सड़कों का निर्माण कार्य परियोजना रिपोर्ट में स्वीकृत मापदंडों के आधार पर निर्मित नहीं की गई यानि उसके धांधाली की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। 20 के लगभग गांवों को तो जोड़ा गया किंतु बहुत सारे गांवों को छोड़ दिया गया। 15 सड़क निर्माण कार्य बीच में ही छोड़ दिये गए यानि उन्हें पूरा नहीं किया गया। साथ ही ये भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि 40 ऐसी सड़कें बनी जिन्हें यातायात के लिए स्वीकृति नहीं मिल पाई क्योंकि इन सड़कों के निर्माण कार्य में धांधली बरती गई। परियोजना रिपोर्ट में निर्दिशित नियमों एवं मापदंडों को नहीं अपनाया गया। सड़क के साथ फुटपाथ, पक्की नालियों, कल्वर्टस, पुल आदि को निर्मित ही नहीं किया गया। बिना ख़ामियों को पूर्ण किए लगभग 77 सड़कों को फाईलों में पूर्ण दिखा दिया गया। इतना ही नहीं, यह भी बड़ा ही चौंकाने वाला तथ्य है कि 13 वर्षों से लागु हो चुकी ऑनलाईन सेवाओं एवं बिलों के भुगतान की प्रक्रिया तथा ऑनलाइन प्रबंधान, देखरेख एवं अकांउटिंग व्यवस्था यानि ओएमएमएएस के होने पर भी किसी भी राज्य ने इसे नहीं अपनाया जिससे पारदर्शिता की संभावनाओं पर संशय होता है। एक भी राज्य ने ऑनलाईन फंड प्रक्रिया को तरहीज़ नहीं दी। साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रलय आज भी किसी भी प्रकार के मासिक कार्य प्रगति रिपोर्ट में निर्णय लेने के लिए मैनुअल प्रक्रिया को ही अपनाकर डिजिटल पारदर्शिता का ढोल पीट रही है। इतना ही नहीं, तीन राज्यों गुजरात, कर्नाटक एवं जम्मु व कश्मीर में तो सूचना तकनीकि के नोडल अधिाकारियों की नियुक्ति तक नहीं की है। जबकि अन्य चार राज्यों अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में तो आंकड़ों की प्रविष्टियों की जांच एवं सत्यापन हेतु कोई पर्यवेक्षी नियंत्रण ही नहीं है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आगाज़ वर्ष 2000 में इस उद्देश्य से किया गया था कि 1,000 लोगों पर हर मौसम में कामयाब व बेहतरीन सड़क का निर्माण 2003 और 500 आबादी के गांवों को 2007 तक पूर्ण किया जाऐगा। 37 संसदीय सदस्सीय पब्लिक अकांउट कमेटी पीएसी की जांच में पाया गया कि कुछ राज्य विनिर्दिश्ट नियमों व प्रक्रिया से भटक गए या इन राज्यों ने इसे नहीं अपनाया। इससे बहुत से गांव एवं लोग या तो सड़क सुविधा से वंचित रह गए या ग़लत तरीक़े से सड़क सुविधा से जुड़े दर्शाए गए।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि 12 राज्यों जिनमें आसाम, झारखंड, मध्यप्रदेश, मेघालय, ओडिशा, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के लगभग 538 कार्य ज़मीन की उपलब्धता के अभाव में आरम्भ ही नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त 11 राज्यों में 372 कार्य ऐसी ही परिस्थितियों में बीच में ही छोड़ दिए गए जिन पर 280.01 करोड़ रुपये को ख़र्चा दिखाया गया। 13 राज्यों में 1,550 कार्य विभिन्न कारणों से छोड़ दिए गए , जैसे कि कार्य अन्य योजना के अंतर्गत किया गया, सड़क का हस्तांतरण किसी अन्य विभाग को कर देना, सामग्री ले जाने के लिए दूरदराज का क्षेत्र होना आदि शामिल है। केरल राज्य की अगर बात करें तो चालू 503 कार्यों में से 40 करोड़ के 56 कार्य लागु करने के लिए ग़ैर संभव बताए गए हैं।

यदि इस योजना के क्रियान्वयन एवं वित्त प्रबन्धान में इतनी ख़ामियां उजागर होती है तो यह चिंता का विषय तो है ही साथ ही डिजिटल युग में पारदर्शिता के दावों पर भी चोट है।

महिलाओं से जुड़े मामलों के लिए देश की पहली आधुनिक फोरेंसिक लैब अब चंडीगढ़ में

यौन उत्पीड़न के लंबित मामलों में डीएनए जांच के लिए फोरेंसिक लैब की कमी से निपटने हेतु अगले तीन माह में ऐसी पांच और लैब खोली जाएगी :

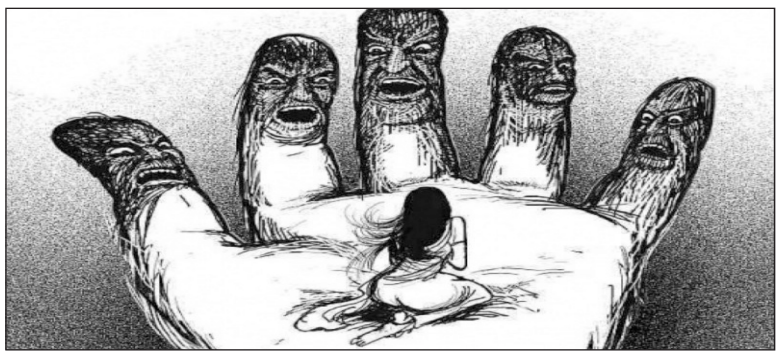

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

महिला और बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने आज केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला सीएसएफएल, चंडीगढ़ के परिसर में सखी सुरक्षा आधुनिक डीएनए फोरेंसिक लैबोरेट्री की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि आपराधिक जांच में फोरेंसिक परीक्षण की अहम भूमिका होती है और देश में यौन उत्पीड़न के लंबित मामलों की फोरेंसिक डीएनए जांच में कमी से निपटने में एडवांस्ड लैब के तौर परा स्थापित की जा रही है और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसी ही लैब शुरु की जाएगी।

सीएसएफएल, चंडीगढ़ की वर्तमान क्षमता 160 मामले प्रतिवर्ष से कम है और सखी सुरक्षा आधुनिक डीएनए फोरेंसिक लैबोरेट्री से यह क्षमता लगभग 2,000 मामले प्रतिवर्ष बढ़ जाएगी। सरकार अगले तीन माह में पांच और आधुनिक फोरेंसिक लैब मुम्बई, चेन्नई, गुवाहाटी, पुणे और भोपाल में खुलेगी, जिससे प्रयोगशालाओं की स्थापना महिला और बाल विकास मंत्रालय के कोश से होगी, जबकि शेष तीन लैब की स्थापना के लिए वित्तिय सहायता गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरने और महिलाओं को समयबद्ध तरीके से न्ययाय दिलाने के लिए डीएनए प्रौद्योगिकी के लिए आधुनिक डीएनए फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है।

दुष्कर्म मामलों के लिए विशेष फोरेंसिक किट : दुश्कर्म मामलों के लिए विशेष फोरेंसिक किट जुलाई तक सभी पुलिस थानों और अस्पतालों में वितरत कर दी जाएगी। फोरेंसिक उत्पीड़न किट का वर्तमान में सीएफएसएल चंडीगढ़ में प्रमाणीकरण किया जा रहा है। ख़राब न होने वाली इन किट का का उपयोग अप्रदूषित सबूत देने के लिए किया जाएगा। इस किट में सबूत एकत्रित करने के लिए आवश्यक उपकरण के साथ लिऐ जाने वाले साक्ष्य/नमूनों की पूरी सूची होगी। इस किट को फोरेंसिक लैब में भेजने से पहले ताला लगाकर बंद कर दिया जाएगा।

आईटीआर फाइल करने का यह आखिरी महीना

आईटीआर फाइल करने का यह आखिरी महीना चल रहा है ऐसे में इससे जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में लोग अभी भी अनजान होंगे। यहां जानें किस तरह के आय पर किस तरह का टैक्स लगाया जाता है।

नई दिल्ली (जेएनएन)। चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 है। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना कई लिहाज से करदाताओं के लिए फायदेमंद होता है। आईटीआर फाइल करने का यह आखिरी महीना चल रहा है ऐसे में इससे जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में लोग अभी भी अनजान होंगे। आईटीआर फॉर्म में अपने वेतन और कमाई का पूरा ब्योरा

देने के अलावा कई ऐसी चीजें भी हैं जिसके बारे में जानना जरुरी है। आपको बता दें कि अपनी कमाई के अलावा अन्य दूसरे माध्यम से हुई आय या उससे हुए नुकसान का ब्योरा देना भी जरूरी है। यहां पर अन्य तरह से होने वाली कमाई का मतलब है, अगर आपने अपनी जमीन या संपत्ति की बिक्री की हो, सोने की बिक्री की हो चाहे शेयर या म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश से होने वाली आय हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस तरह की कमाई का ब्योरा भी आपको अपने आईटीआर फॉर्म में शामिल करना चाहिए। यहां हम आपको बता रहे हैं किस तरह के आय पर किस तरह का टैक्स लगाया जाता है।

बिना फॉर्म 16, कैसे करें रिटर्न फाइल यह भी पढ़ें दो तरह से कर लगेगा सावधान: ITR भरने के लिए 20 दिन बाकी, तय तारीख के बाद देनी होगी पेनल्टी सोना, शेयर या इसी प्रकार के अन्य तरह से होने वाले लाभ पर दो तरह से टैक्स लगाया जाता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ये दोनों प्रकार के टैक्स उसे रखे जाने की समय-सीमा पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से इस प्रकार की कमाई से आने वाली आय की गणना बेची गई राशि से खरीद लागत को घटाकर किया जाता है।

IIRD हम जानते हैं गाँव को बेहतर
MISSION RIEV
Ruralising India- Empowering Villages
सबका साथ ही
मिशन की सफलता है क्योंकि
हम जानते हैं गाँव को बेहतर
कि दुनिया देखती रह जाए

फ्रांस को पीछे छोड़ भारत बना दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था नोटबंदी और जीएसटी के असर धीरे-धीरे उबर रही है। इसी का असर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। विश्व बैंक ने 2017 के अपडेटेड आंकड़े पेश किए हैं। विश्व बैंक की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने फ्रांस को 7वें पायदान पर धकेल दिया है। इस रिपोर्ट में भारत जहां छठे पायदान पर है। वहीं, इस टेबल में सबसे आगे यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी है। चीन ने इस टेबल में दूसरा रैंक हासिल किया है। चीन के बाद जापान, जर्मनी और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था काबिज हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर पेश किए गए ये आंकड़े 2017 में किए गए रिफॉर्म और बदलावों के आधार पर है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के अंत तक भारत की अर्थव्यवस्था 2.597 खरब डॉलर की थी। इसी दौरान फ्रांस की इकोनॉमी 2.582 खबर डॉलर के बराबर थी। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा, कुछ तिमाही तक भारत की इकोनॉमी में गिरावट रही है। लेकिन बाद में मोदी सरकार की तरफ से शुरू किए गए रिफॉर्म्स ने सूरत बदली और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली है।

प्रति व्यक्ति आय जीडीपी की बात करें तो इस मामले में भारत फ्रांस से अभी भी पीछे है. फ्रांस की प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत से 20 गुना ज्यादा है। इसके लिए भारत की जनसंख्या का ज्यादा होना वजह है। जहां भारत की जनसंख्या 134 करोड़ के पार है। वहीं, फ्रांस की जनसंख्या महज 6.7 करोड़ है। विश्व बैंक के मुताबिक भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई बढ़त का सहारा मिला है। बैंक ने कहा कि भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार अगर धीमी हुई है, तो इसके लिए नोटबंदी और जीएसटी जिम्मेदार थी। हालांकि संपूर्ण रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था ने तेज विकास किया है. पिछले 10 साल में भारत की जीडीपी का आकार दोगुना हुआ है

15 जुलाई से शुरू होगी श्रीखंड यात्रा

इस बार श्रीखंड यात्रा पंद्रह जुलाई से शुरू हो रही है जो 31 जुलाई तक चलेगी। कुल्लू निरमंड की कुर्पण घाटी में समुद्रतल से लगभग 18570 फुट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड कैलाश को कुदरत का करिशमा कहा जाता है। देश की सबसे कठिनतम और रोमांचकारी तीर्थ यात्राओं में शुमार श्रीखंड कैलाश के लिए इस वर्ष श्रद्धालुओं का भारी उत्साह दिख रहा है। सरकार ने यात्रा को ट्रस्ट के अधीन लाया है, जिसका जिम्मा प्रशासन को सौंपा गया है। पंद्रह जुलाई को यात्रा के बेस कैंप सिंहगाड से श्रीखंड यात्रा के पहले जत्थे को विधिवत रूप से रवाना किया जाएगा। मार्ग में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन और श्रीखंड सेवादल समितियों द्वारा खाने-पीने व रहने की नि:शुल्क व्यवस्था की गई है। बेस कैंप सिंहगाड, थाचडू और भीमडवार में चिकित्सा शिविर की सुविधा भी मुहैया करवाई गई है।

बीएसएनएल ने भारत की पहली इंटरनेट टेलीफोनी सेवा आरंभ की

सरकारी दूरसंचार सेवा प्रदाता भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने 11 जुलाई 2018 से देश में पहली बार इंटरनेट टेलीफोनी सेवा शुरू की है। संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने बीएसएनएल के कॉर्पोरेट कार्यालय में एक समारोह में यह सेवा लाँच की. इसे 'विंग्स' नाम दिया गया है।

बीएसएनएल कंपनी देश में यह सेवा देने वाली पहली कंपनी है। अन्य कंपनियाँ भी इस क्षेत्र में आ रही हैं।

इंटरनेट टेलीफोनी सेवा के बारे में जानकारी बीएसएनएल के उपभोक्ता अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप पर 'एसआईपी क्लाइंट' नामक एप्प डाउनलोड कर अपने डिवाइस से इंटरनेट कॉलिग कर सकेंगे।

इस सेवा के इस्तेमाल के लिए किसी सिम कार्ड या मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं होगी। विश्व में जहाँ कहीं भी ग्राहक के डिवाइस में वाई-फाई या कोई अन्य इंटरनेट कनेक्शन है, वह इस एप्प के माध्यम से कॉलिग कर सकेगा। यह एप्प वीडियो कॉलिंग और कांफ्रेंस कॉलिंग को भी सपोर्ट करता है। उपभोक्ता अपने डिवाइस में मौजूद संपर्क सूची का भी इस्तेमाल कर सकेगा। इंटरनेट टेलीफोनी नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क का इस्तेमाल करता है जो कॉलिंग और डाटा दोनों के लिए उपयोगी है।

इससे ग्राहक अपने लैंडलाइन नंबर को भी 'एसआईपी क्लाइंट' ऐप से जोड़ सकता है। कॉलिंग के लिए इंटरनेट कनेक्शन बीएसएनएल का होना जरूरी नहीं है।

इंटरनेट टेलीफोनी का लाभ

इंटरनेट टेलीफोनी एप्प 'विंग्स' को बीएसएनएल द्वारा जारी एक मोबाइल नंबर से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन कंपनी के 'विंग्स' एप्प के उपभोक्ता के लिए उसे मोबाइल या लैंडलाइन का अलग से कनेक्शन नहीं लेना होगा। बीएसएनएल के मौजूदा लैंडलाइन ग्राहकों को एक अलग लाभ होगा। वे अपनी जगह पर निर्भर किए बिना एप्प पर इनकॉमिंग कॉल प्राप्त कर सकेंगे।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की सूची में भारत 57वें स्थान पर

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) की सूची में भारत 57वें नंबर पर है, पिछले साल भारत 60वें नंबर पर था। भारत की स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है। वर्ष 2015 में यह 81वें स्थान पर था।

चीन विश्व के शीर्ष 20 सर्वाधिक नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। यह सालाना रैकिगं कॉर्नेल विश्वविद्यालय, आईएनएसईएडी और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा 10 जुलाई 2018 को प्रकाशित की गई। मुख्य तथ्य:

स्विटजरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) में शीर्ष स्थान पर बरकरार है।

मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत शीर्ष पर है। जबकि दुनिया भर की रैकिंग में भारत 57वें स्थान पर है।

भारत ने कई महत्वपूर्ण सूचकांकों की रैंकिग में सुधार किया है। उत्पादकता वृद्धि और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और सेवाओं के निर्यात क्षेत्र में भी उसने रैकिंग सुधारी है।

पिछले साल (वर्ष 2017) की रैकिंग में भारत और तीन स्थान नीचे 60 पर था। मध्य और दक्षिण एशिया में भारत के बाद दूसरे स्थान पर ईरान और तीसरे स्थान पर कज़ाकिस्तान है।

जीआईआई 2018 के शीर्ष 10 देशों में स्विटजरलैंड के बाद नीदरलैंड, स्वीडन, ब्रिटेन, सिंगापुर, अमेरिका, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी और आयरलैंड शामिल हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष 5 देश: 1. स्विट्जरलैंड, 2. नीदरलैंड,
3. स्वीडन, 4. यूनाइटेड किंगडम
5. सिंगापुर

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई)

जीआईआई में 80 संकेतकों पर 126 अर्थ व्यवस्थाओं की रैंकिंग की गई, जिसमें बौद्धिक संपदा फाइलिंग दर से लेकर मोबाइल एप्लिकेशन निर्माण, शिक्षा खर्च और वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकाशनों तक को शामिल किया गया।

चीन इस साल (वर्ष 2018) इस रैकिंग में 17वें स्थान पर रहा, जोकि उसकी अर्थव्यवस्था की सफलता दर्शाती है। वहां की सरकार की नीतियों में शोध और विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

जीआईआई इंडेक्स के अनुसार मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत सबसे इनोवेटिव देश है।

आईआईआरडी कनार्टक में बनाएगा मल्टी पर्पज स्पोर्टस कॉम्पलैक्स

आईआईआरडी हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर दूसरे राज्य में भी अपनी विशेष पहचान बना चुका है। यही कारण है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी आईआईआरडी के साथ मिलकर काम करने के लिए आगे आ रही हैं। इसका ताजा उदहारण आईआईआरडी की ओर से कर्नाटक में बनाया जा रहा मल्टी पर्पज स्पोर्टस कांपलैक्स है। ओएनजीसी के सहयोग से आईआईआरडी द्वारा यह कांपलैक्स कर्नाटक के धारवाड़ में बनाया जाएगा। इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और अब जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू किया जा रहा है। 6495 सक्वेयर मीटर पर बनने वाले इस कांपलैक्स में युवाओं और अन्य आयुवर्ग के लिए विभिन्न खेल गतिविधियों की सुविधा होगी और साथ ही फिट रहने के लिए जिम और अन्य अत्याधुनिक तकनीक से लैस उपकरण भी होंगे। कर्नाटक में यह प्रोजेक्ट इस बात की पुष्टि करता है कि आईआईआरडी हिमाचल में ही नहीं बल्कि प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी विश्वसनीय कंपनी के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है।

भारत यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का 69वां शेयर धारक बना

द रीव टाइम्स ब्यूरो

European Bank for Reconstruction and Development

भारत औपचारिक रूप से 11 जुलाई 2018 को यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (ईबीआरडी) का 69वां शेयरधारक बन गया है।

इससे बैंक के संचालन क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के साथ और अधिक संयुक्त निवेश का रास्ता साफ हो गया है। सदस्यता से जुड़ी सारी प्रक्रिया इस सप्ताह पूरी हो गई थी।

कब क्या हुआ

भारत सरकार ने दिसंबर 2017 में ईबीआरडी सदस्यता के लिए आवेदन किया था।

ईबीआरडी ने जून 2018 में मुंबई में अपना उद्घाटन व्यापार मंच आयोजित किया।

यह ईबीआरडी के कार्य क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त निवेश में वृद्धि करेगा।

प्रभाव

ईबीआरडी की सदस्यता से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि में और अधिक निखार आएगा तथा इसके आर्थिक हितों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

ईबीआरडी के संचालन वाले देशों तथा उसके क्षेत्र ज्ञान तक भारत की पहुंच निवेश तथा अवसरों को बढ़ाएगी।

भारत के निवेश अवसरों में बढ़ोत्तरी होगी. इस सदस्यता से विनिर्माण, सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी और ऊर्जा में सह-वित्तपोषण अवसरों के जरिए भारत और ईबीआरडी के बीच सहयोग के अवसर बढेंगे।

ईबीआरडी के महत्वपूर्ण कार्यों में अपने संचालन के देशों में निजी क्षेत्र का विकास करना शामिल है।

इस सदस्यता से भारत को निजी क्षेत्र के विकास को लाभान्वित करने के लिए बैंक की तकनीकी सहायता तथा क्षेत्रीय ज्ञान से मदद मिलेगी।

इससे देश में निवेश का माहौल बनाने में योगदान मिलेगा।

ईबीआरडी की सदस्यता से भारतीय फर्मों की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ेगी और व्यापार के अवसरों, खरीद कार्यकलापों, परामर्श कार्यों आदि में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनकी पहुँच बढ़ेगी।

इससे एक ओर तो भारतीय पेशेवरों के लिए नए क्षेत्र खुलेंगे और दूसरी ओर भारतीय निर्यातकों को भी लाभ मिलेगा।

बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों से रोजगार सृजन क्षमता में विस्तार होगा। इससे भारतीय नागरिक भी इस बैंक में रोज़गार के अवसर प्राप्त कर सकेंगे।

यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक

ईबीआरडी एक बहुपक्षीय विकास निवेश बैंक है। जर्मनी के एकीकरण के बाद यूरोप में निजी और उद्यमशीलता अभियान को बढ़ावा देने के लिए 1991 में इस बैंक की स्थापना की गई थी।

बैंक का मुख्यालय लंदन में है। यह बैंक 38 उभरती हुई अर्थव्यस्थाओं में निवेश करता है। यह पहले पूर्व साम्यवादी राज्यों को शीत युद्ध के बाद अपनी अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करने में सहायता करता था बाद में 30 से अधिक देशों में मध्य यूरोप से मध्य एशिया तक विकास से जुडी सहायता करने के लिए इसका विस्तार किया गया।

यह उन देशों में ही काम करता है जो बाजार अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण के लिए उपकरण के रूप में निवेश का उपयोग करके लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए काम करते हैं।

भारत दुनिया की चौथी बड़ी सैन्य शक्ति

भारत दुनिया की चौथी बड़ी सैन्य शक्ति, पाकिस्तान हमसे 13 स्थान पीछे अमेरिका के पास सबसे ज्यादा लड़ाकू विमान देशों की सैन्य शक्ति का हर साल आकलन करने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर ने 2018 का इंडेक्स जारी किया ।

ग्लोबल फायर पावर ने 136 देशों की सूची जारी की पड़ोसी देशों में चीन तीसरे, नेपाल 101वें, भूटान 136वें और बांग्लादेश 56वें नंबर पर भारत और चीन की रैंकिंग बरकरार (पाकिस्तान, नेपाल, भूटान की रैंक में गिरावट) अमेरिका के पास विमान, रूस के पास टैंक और उत्तर कोरिया के पास युद्ध पोत सबसे ज्यादा सैन्य ताकत के मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर बना हुआ है। पड़ोसी देश चीन हमसे आगे है और दूसरे नंबर पर है। लेकिन पाकिस्तान की सैन्य ताकत में गिरावट आई है। पिछले साल वह 13वें नंबर पर था। इस साल 17वीं पायदान पर है। पाकिस्तान पहले भारत से नौ स्थान पीछे था। अब 13 स्थान पीछे है। देशों की सैन्य ताकत का हर साल आकलन करने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर के 2018 इंडेक्स में यह जानकारी दी गई है।

ग्लोबल फायर पावर ने 2018 के इंडेक्स के लिए 136 देशों की सैन्य ताकत का आंकलन किया। इसमें देशों की भौगौलिक स्थिति, साजो-सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्षमता, प्राकृतिक संसाधन और औद्योगिक समर्थन के आधार पर देशों को नंबर दिए गए। देशों की आर्थिक स्थिरता और उनके रक्षा बजट को इंडेक्स में महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया गया। इंडेक्स में देशों की परमाणु ताकत और वहां के राजनीतिक नेतृत्व को शामिल नहीं किया गया।

सबसे ताकतवर देश

सेना, नौसेना और वायुसेना की ताकत मिलाकर

स्थान	देश
पहला	अमेरिका
दूसरा	रूस
तीसरा	चीन
चौथा	भारत
पांचवां	फ्रांस
17वां	पाकिस्तान

चीन के पास सबसे ज्यादा सैनिक

देश	फौज
चीन	21.8 लाख
भारत	13.6 लाख
अमेरिका	12.8 लाख
रूस	10 लाख
उत्तर कोरिया	9.45 लाख
पाकिस्तान	6.37 लाख

अमेरिका के पास चीन से चार गुना विमान

देश	विमान
अमेरिका	13362
रूस	3914
चीन	3035

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की सूची में भारत 57वें स्थान पर

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) की सूची में भारत 57वें नंबर पर है, पिछले साल भारत 60वें नंबर पर था। भारत की स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है। वर्ष 2015 में यह 81वें स्थान पर था।

चीन विश्व के शीर्ष 20 सर्वाधिक नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। यह सालाना रैंकिगं कॉर्नेल विश्वविद्यालय, आईएनएसईएडी और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा 10 जुलाई 2018 को प्रकाशित की गई।

मुख्य तथ्य:

स्विटजरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) में शीर्ष स्थान पर बरकरार है। मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत शीर्ष पर है। जबकि दुनिया भर की रैंकिंग में भारत 57वें स्थान पर है।

भारत ने कई महत्वपूर्ण सूचकांकों की रैंकिग में सुधार किया है। उत्पादकता वृद्धि और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और सेवाओं के निर्यात क्षेत्र में भी उसने रैंकिंग सुधारी है।

पिछले साल (वर्ष 2017) की रैंकिंग में भारत और तीन स्थान नीचे 60 पर था। मध्य और दक्षिण एशिया में भारत के बाद दूसरे स्थान पर ईरान और तीसरे स्थान पर कजाकिस्तान है।

जीआईआई 2018 के शीर्ष 10 देशों में स्विटजरलैंड के बाद नीदरलैंड, स्वीडन, ब्रिटेन, सिंगापुर, अमेरिका, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी और आयरलैंड शामिल हैं।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष 5 देश:

1. स्विट्जरलैंड, 2. नीदरलैंड,
3. स्वीडन, 4. यूनाइटेड किंगडम
5. सिंगापुर

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई)

जीआईआई में 80 संकेतकों पर 126 अर्थ व्यवस्थाओं की रैंकिंग की गई, जिसमें बौद्धिक संपदा फाइलिंग दर से लेकर मोबाइल एप्लिकेशन निर्माण, शिक्षा खर्च और वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकाशनों तक को शामिल किया गया।

जीआईआई इंडेक्स के अनुसार मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत सबसे इनोवेटिव देश है।

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापारिक समझौते

केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री किम हियूंन चांग ने 09 जुलाई 2018 को दिल्ली में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये। इस अवसर पर सुरेश प्रभु ने कहा कि यह व्यापारिक समझौते दोनों देशों के रिश्ते को आगे ले जाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे।

भारत और दक्षिण कोरिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पांच सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून के साथ आए शिष्ट मंडल में उनके मंत्री परिषद के वरिष्ठ सदस्यों, अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं.

हस्ताक्षरित समझौते

सहयोग कार्यक्रम 2018-21

भविष्य रणनीतिक समूह का गठन

जैव प्रौद्योगिकी एवं जैव अर्थव्यवस्था में सहयोग

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत की ओर से और दक्षिण कोरिया के विज्ञान मंत्री यू यंग मीन ने 2018-21 मे सहयोग कार्यक्रम से संबंधित तीन सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किये। दो अन्य सहमति पत्रों पर भारत की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद तथा आई आई टी मुंबई और कोरिया के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने हस्तारक्षर किये।

सहयोग कार्यक्रम 2018-21 पर समझौता ज्ञापन

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवीनता में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने 2018-21 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के कार्यक्रम को नवीनीकृत किया।

जैव प्रौद्योगिकी और जैव अर्थव्यवस्था में सहयोग पर समझौता ज्ञापन

जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों पक्षों द्वारा स्वास्थ्य और चिकित्सा, कृषि-मत्स्य उत्पादों, पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के समाधान हेतु सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की गई है।

भविष्य रणनीतिक समूह का गठन

भविष्य रणनीतिक समूह की स्थापना के लिए भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा कोरिया के वाणिज्य मंत्रालय के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

भविष्य रणनीतिक समूह दोनों देशों के आर्थिक लाभ के लिए मिलकर योजनाओं को क्रियान्वित करेगा।

भारत-कोरिया संयुक्त नेटवर्क केन्द्रों की स्थापना

भारत और कोरिया ने साइबर फिजिकल सिस्टम, आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, इन्टरनेट, कृषि, ऊर्जा, जल और परिवहन पर आधारित भारत-कोरिया संयुक्त नेटवर्क केंद्रों को संयुक्त रूप से स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।

केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री किम हियूंन चांग ने 09 जुलाई 2018 को दिल्ली में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये। इस अवसर पर सुरेश प्रभु ने कहा कि यह व्यापारिक समझौते दोनों देशों के रिश्ते को आगे ले जाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे।

भारत और दक्षिण कोरिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पांच सहमति पत्रों पर हस्तोक्षर किये। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून के साथ आए शिष्ट मंडल में उनके मंत्री परिषद के वरिष्ठ सदस्यो, अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं।

FIFA World CUP 2018

द रीव टाइम्स ब्यूरो

The 2018 FIFA World Cup Final will be the 21st final of the FIFA World Cup, a quadrennial tournament contested by the men's national teams of the member associations of FIFA. The match will be held at the Luzhniki Stadium in Moscow, Russia, on 15 July 2018 and will be contested by France and Croatia.

After Uruguay and Brazil were eliminated in the quarter-finals, a European side was ensured to win the World Cup for a fourth consecutive tournament. The match is also the ninth all-European World Cup final, having most recently occurred in 2006 and 2010. The match is the third World Cup final for France, first appearing in 1998 final as hosts, winning 3–0 against reigning champions Brazil. France also contested 2006 final, where they lost to Italy in a penalty shoot-out following a 1–1 draw.[26][27] Only Germany (eight) and Italy (six) have reached more finals among European nations.

The winners of the World Cup will qualify for the 2021 FIFA Confederations Cup.

FIFA World Cup Trivia

- The first world cup soccer match kicked off on July 13th, 1930 with France beating Mexico 4 to 1 (more on Uruguay 1930)
- There were a total of 13 teams in the first World Cup. Besides the host Uruguay, there were Argentina, Belgium, Brazil, Bolivia, Chile, France, Mexico, Paraguay, Peru, Romania, the United States and Yugoslavia.
- Did you know that South American and European countries have won the World Cup 9 times and 10 times respectively? There has been no other continent which has produced a World Cup Champion.
- World Cup Winners (total number by country): Brazil 5, Germany 4, Italy 4, Uruguay 2, Argentina 2, England 1, France 1 and Spain 1.
- Who says there is no such thing as home advantage? Out of the 20 World Cups so far, six have been won by the host country.
- Because of World War II, the World Cup was not held between 1938 and 1950. As a result, Italy were the reigning World Cup Champions for a record 16 years (from 1932 until 1950).
- Bora Milutinovic coached in every tournament between 1986 and 2002 - but for different teams: Mexico, Costa Rica, USA, Nigeria and China.
- Six teams have been unbeaten but not the champions in the same finals. Those unbeaten teams are: Scotland in 1974 (1 win, 2 draws), Brazil in 1978 (4 wins, 3 draws), England in 1982 (3 wins, 2 draws), Cameroon in 1982 (3 draws), Belgium in 1998 (3 draws) and New Zealand 2010 (3 draws).
- The only man reportedly to have played both World Cup Football and World Cup Cricket is Viv Richards - Antigua and Barbuda at football (in the qualifiers only) and West Indies at cricket. He actually he played for Antigua and Barbuda in a qualifying round of the CONCACAF championship, which is in turn the qualifier to get into the World Cup of 1974. Someone who did actually achieve this unique double is Australian Ellyse Perry, who appeared in the final rounds of both cricket (2009) and football World Cups (2011).
- Shirt swapping was once officially prohibited in 1986 because FIFA did not want players to 'bare their chests' on the field.
- The highest attendance at a World Cup match was 199,854 at the Maracana Stadium in Rio de Janerio for the 1950 decider between Uraguay and Brazil.
- The record for the lowest attendance was for the match between Peru and Romania in 1930, where just 300 people watched the game.
- In the 1950 finals, there was only a final pool to determine the winner, without a knock-out Final as has been held in other Finals series.
- The most common surname of World Cup players is Gonzalez or Gonzales. The most common score in a World Cup finals match is 1-0.
- The only manager to win successive World Cups was Italy's Vittorio Pozzo in 1934 and 1938.
- The 1966 World Cup is the only World Cup to have been boycotted by an entire continent, in protest to having to play off against the Asian champion for the one place in the finals, and also against the re-admission of South Africa to FIFA.
- Brazil is the only country to have appeared in every tournament, 21 finals tournaments from 1930 to 2018.
- The fastest red card was given to Uruguay defender Jose Batista, who was shown a red card against Scotland at the 1986 World Cup at the 52nd-second mark. Actually, the foul was committed in the 39th second and it took the referee 13 seconds to show the card.
- The 2010 World Cup was the first with no debutant associations, although two of the qualifiers (Slovakia and Serbia) had previously appeared only as parts of former competing nations.
- No host country had ever been eliminated in the first round - until South Africa in 2010.
- It can be claimed that the 2018 World Cup will be held in both Europe and Asia, as some matches will be held in the Russian city of Yekaterinburg, considered to be part of Asia.
- Iceland qualified for the first time in 2018, becoming the smallest country (in terms of population) to reach the World Cup.

इजराइल ने प्रदूषण फैलाने वाली कम्पनियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित

द रीव टाइम्स ब्यूरो

इजरायली मंत्रिस्तरीय समिति द्वारा पारित विधेयक के अनुसार अब आम नागरिक एवं एनजीओ प्रदूषण फैलाने वाली कम्पनियों के खिलाफ सिविल कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं।

इजराइल सरकार द्वारा 08 जुलाई 2018 को यह विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक से उन दिग्गज कम्पनियों पर दबाव बनाया जा सकेगा जो राज्य द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु बनाए गये नियमों का पालन नहीं करते ।

पर्यावरण समूह के चेयरमैन एवं इजराइल की संसद सदस्य डोव खेनिन के अनुसार, पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा उठाये यह कदम आवश्यक हैं लेकिन काफी नहीं हैं। इजराइल में पिछले कुछ वर्षों में प्रदूषण के कारण दो ऐसे भयावह हादसे हुए हैं जिनके लिए एइलाट-एश्केलों पाइप लाइन एवं इजराइल केमिकल लिमिटेड को दोषी पाया गया था। माना जा रहा है कि इजराइल केमिकल्स पिछले 20 वर्षों से पर्यावरण प्रदूषण को लेकर जारी की गई चेतावनी को नजरअंदाज कर रहा था।

डोव खेनिन के अनुसार, यह विधेयक हमें नई शक्ति प्रदान करेगा तथा पर्यावरण की स्थिति में सुधार हेतु अवसर प्रदान करेगा। प्रदूषण का प्रमुख कारण कम्पनियों की आर्थिक लाभ की लालसा रहा है।

इजराइल में प्रदूषण

इजराइल की तीसरी सबसे बड़ी नदी किशोन नदी प्रदूषण का सबसे बड़ा उदहारण है। वर्ष 2010 में इजराइल पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि देश के मध्य भाग में मौजूद बहुत से कुओं की जांच से पता चला है कि उनमें प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है।

इजराइल लगभग बीस हजार वर्ग किलोमीटर में स्थित देश है जिसके पास एक सीमित मात्रा में संसाधान मौजूद हैं। सीमित स्थान, अर्द-शुष्क जलवायु, सघन जनसंख्या एवं कम होते प्राकृतिक संसाधानों के कारण इजराइल में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है।

Mission RIEV finds mention at 8th AMCDRR -Mangolia

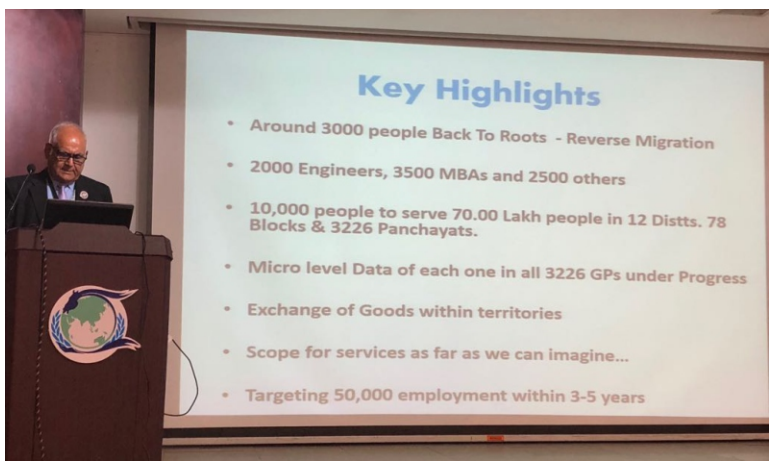

- After being showcased at UN meet at Manila, Mission RIEV was part of discussion and deliberation at recently held three-day Asian Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction (AMCDRR), Ulaanbaatar, Magnolia on July 3, 2018. Brig. B K Khanna, representing ARISE UNISDR Mission of FICCI and one of the Director of IIRD Shimla, spoke about Mission RIEV objectives and how its making an impact in 3226 panchayats of Himachal Pradesh. "Mission RIEV in Himachal Pradesh is an exemplary initiative, which is helping in self-sustenance of villagers within village and helping in creating employment within villages to 10,000 people across Himachal Pradesh.
- It has not only helped in generating employment and revenue within village but also helped in reverse migration of people from cities to villages. And all this without any support from any government or private financing, a successful mission started with zero budget, said Brig B K Khanna".

The Mission is also manadated with the role of first response unit for any kind of the disaster situations in the villages across Himachal Pardesh through participatory actions.

The event saw participation of 3000 plus, which included representatives from over 50 countries and 1,500 organizations, Brig. B K Khanna, one of the Directors of Institute for Integrated Rural Development (IIRD) Shimla and representing ARISE UNISDR Mission India. The theme of AMCDRR 2018 is, 'Preventing Disaster Risk: Protecting Sustainable Development' and our Government endorses this theme having enthusiastically adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development and noting the critical role that Disaster Risk Reduction has in protecting our current and future development progress.

AMCDRR 2018 is the second ministerial conference since the advent of the Sendai Framework in March 2015 and as such it provides a number of key opportunities

मिशन रीव सचिवालय

Governing Board of Mission RIEV

DR LC SHARMA
MD IIRD -Mentor

MR SK SHARMA
Co-Director IIRD

MRS SUSHMA SHARMA
CEO Hind Sewa Sangathan

MR ANAND NAIR
Director Flyers Group Pvt Ltd

Mrs MEHREEN IQBAL
CEO IIRD Foundation for Sustainable Development

Mission RIEV Secretariate

N.K. SHARMA
Mission Head-RIEV

GAURAV DWIVEDI
Senior Operating Officer

SURENDER KUMAR
State Coordinator

Deepika Sharma
Programme Officer/ Jr Scientist

Harish Godara
BDM Agriculture

Sameer Panta
Operations Head

Bhavna Rana
Program Associate

Meenakshi Rangta
Program Associate

Deepa Negi
Program Associate

Kumari Neelam
Incharge GMO

द रीव टाइम्स
संस्थापकः डॉ. एल.सी. शर्मा, द रीव टाइम्स पब्लिकेशन के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक
श्री प्रदीप कुमार जरेट द्वारा एसोसिएट प्रैस सायबू निवास समीप सेक्टर -2 , बस स्टैड मिडल मार्केट न्यू शिमला-9, हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुद्रित

प्रधान सम्पादकः डा. एल.सी. शर्मा, प्रबन्ध सम्पादकः आनन्द नायर
फोन न. 0177 2640761, मेलः editor@themissionriev.com
RNI Reference No. 1328500